● वर्ष-3
● अंक-307
रायपुर, मंगलवार
06 अगस्त 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› शिवजी को ऐसे करें अभिषेक

बांग्लादेश में हिंसाः सेना ने संभाली कमान

ढाकाः बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया और वो देश छोड़कर भाग गई हैं। इसे हसीना सरकार का तख्तापलट माना जा रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने स्थानीय सूत्रों के हवाले से बताया कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को सोमवार को एक सैन्य हेलीकॉप्टर से भारत लाया गया, क्योंकि सरकार विरोधी आंदोलन के बीच हजारों प्रदर्शनकारियों ने उनके इस्तीफे की मांग की थी। दूसरी तरफ बांग्लादेशी दैनिक प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम के जाने के बाद अब अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी।

मीडिया में आयी कई खबरों में यह दावा किया गया है सेना प्रमुख वकार उज जमां ने कहा कि शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और अंतरिम सरकार शासन की बागडोर संभालेगी। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा है कि उन्होंने राजनीतिक दलों के नेताओं से बात की है और उन्हें बताया कि सेना कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। हालांकि, उनके देश से बाहर जाने के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गयी है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद देश की कमान सेना ने संभाल ली है। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां ने सोमवार को यहां यह घोषणा की। हसीना के देश छोड़कर चले जाने की खबरों के बीच उन्होंने टेलीविजन पर दिए गए अपने संबोधन में कहा, मैं (देश की) सारी जिम्मेदारी ले रहा हूं। कृपया सहयोग करें। ऐसी अपुष्ट खबरें है कि वह (हसीना) भारत के किसी शहर के लिये रवाना हो गई हैं। इस बीच देश भर में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है । सेना प्रमुख ने कहा कि उन्होंने राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की और उन्हें बताया कि सेना कानून-व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालेगी। देश भर में विरोध प्रदर्शनों के बीच जनरल ने कहा कि उन्होंने सेना और पुलिस दोनों से गोली न चलाने को कहा है। पिछले दो दिनों में शेख हसीना सरकार के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों में 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। देश में विवादास्पद आरक्षण प्रणाली को लेकर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसके तहत 1971 के मुक्ति संग्राम में लड़ने वालों के परिवारों के लिए 30 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित हैं। जमां ने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और हिंसा बंद करने का आग्रह किया। हसीना एक हेलीकॉप्टर से त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के लिए रवाना हुई हैं। एसोसिएटेड प्रेस ने बताया कि हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन कोई अन्य जानकारियां नहीं दी। बहरहाल, विदेश मंत्रालय या अगरतला में स्थानीय अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि करने से इनकार कर दिया है। त्रिपुरा के गृह सचिव पी. के. चक्रवर्ती ने बताया, ''हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

मोदी ने बुलाई हाईलेवल मीटिंग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के मौजूदा हालातों को लेकर बैठक कर रहे हैं। बैठ प्रधानमंत्री आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर हो रही है। सूत्रों के मुताबिक, बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पीएमओ के अधिकारी मौजूद हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। बांग्लादेश की नेता शेख हसीना का सैन्य विमान उनके देश में उथल-पुथल के बीच दिल्ली से लगे गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस पर उतरा। वह भारत के रास्ते लंदन जा रही हैं। माना जाता है कि जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को पड़ोसी देश में बदलते घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी। हालांकि, बैठक के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी।

विदेश मंत्री से मिले राहुल

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और बांग्लादेश के घटनाक्रम पर चर्चा की। कांग्रेस सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने बांग्लादेश के ताजा घटनाक्रम पर चर्चा की, हालांकि इस बारे में विस्तार से नहीं बताया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश में कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन के बाद सोमवार को पद से इस्तीफा दे दिया। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां ने सोमवार को कहा कि अब अंतरिम सरकार कार्यभार संभालेगी। बांग्लादेश में राजनीतिक तख्तापलट के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक, डोभाल ने बांग्लादेश के हालातों के बारे में जानकारी ली है। इससे पहले शेख हसीना विशेष विमान से 5.36 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची। हसीना अभी हिंडन एयरबेस पर ही रुकी हुई हैं। सूत्र बताते हैं कि वह लंदन रवाना हो सकती हैं।

बांग्लादेश के हालातों पर नई दिल्ली की नजर

भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि ढाका में तेजी से बदल रहे घटनाक्रम पर नई दिल्ली करीबी नजर रखे हुए है। बांग्लादेश में जारी घटनाक्रम पर भारत की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ढाका में, बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकार-उज-जमां ने कहा कि हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और एक अंतरिम सरकार कार्यभार संभालने जा रही है। सेना प्रमुख ने टेलीविजन पर अपने संबोधन में कहा, मैं (देश की) सारी जिम्मेदारी ले रहा हूं।

मेघालय ने बॉर्डर पर लगाया नाइट कर्फ्यू, सीमा पर हाई अलर्ट

शिलांग। मेघालय के उपमुख्यमंत्री प्रेस्टोन तिनसोंग ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश में मौजूदा हालात के मद्देनजर उसके साथ लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सीमा के 444 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में कर्फ्यू अगले आदेश तक रोजाना शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक लागू रहेगा। यह निर्णय सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के कर्मियों और मेघालय पुलिस के साथ एक तत्काल बैठक के दौरान लिया गया। तिनसोंग ने कहा, ''अस्थिर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा पर रात्रि कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने सोमवार को बांग्लादेश में हुए घटनाक्रम के मद्देनजर 4,096 किलोमीटर लंबी भारत-बांग्लादेश सीमा पर अपनी सभी यूनिट के लिए सोमवार को हाई अलर्ट जारी किया।

शेख हसीना से मिले डोभाल

बांग्लादेश में राजनीतिक तख्तापलट के बीच भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक, डोभाल ने बांग्लादेश के हालातों के बारे में जानकारी ली है। इससे पहले शेख हसीना विशेष विमान से 5.36 बजे गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पहुंची। हसीना अभी हिंडन एयरबेस पर ही रुकी हुई हैं।

धारा 370 हटाने के 5वीं वर्षगांठ

जमीनी स्तर पर मजबूत हुआ लोकतंत्रः शाह

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से वंचित वर्गों के लिए सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई है और क्षेत्र में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के पांच साल पूरे होने पर, शाह ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं ने सामाजिक-आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्रेरित किया है, जिससे शांति और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयास एक शानदार प्रयास बन गए हैं।

शाह ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि आज पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 और 35ए को ऐतिहासिक रूप से हटाए जाने के पांच साल पूरे हो गए हैं। इस परिवर्तनकारी निर्णय ने हाशिए पर मौजूद वर्गों के सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की है और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत किया है।

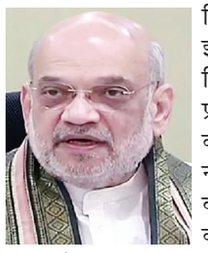

उन्होंने आगे लिखा कि क्षेत्र के युवाओं ने सामाजिक-आर्थिक विकास और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को प्रेरित किया है, जिससे शांति और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के मोदी सरकार के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। भाजपा नेता ने कहा कि हम इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए मोदी को धन्यवाद देते हैं और क्षेत्र की आकांक्षाओं और परिवर्तनकारी प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने के पांच साल पूरा होने के मौके पर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह कदम देश के लोकतंत्र और जम्मू-कश्मीर के लिए ठीक नहीं था। इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रतिवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए यह कदम उठाया था।

मेहदी ने लोकसभा में मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के नियंत्रणाधीन अनुदान की मांगों पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा, ''जो पांच अगस्त को हुआ था, वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था...किसी पार्टी के लिए ठीक हो सकता है, लेकिन इस सदन और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं था।''

कागज लेकर आइए, सरकार पैसा देने को तैयारःसीतारमण

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सहारा की दो योजनाओं के तहत निवेशकों को कुल 25,000 करोड़ रुपये में से अब तक केवल 138.07 करोड़ रुपये वापस किये गये हैं। निचले सदन में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, सीतारमण ने कहा कि अब तक दावों की संख्या 19,650 है। उनके मुताबिक, इन दावों में से 17,250 दावों का निपटारा कर दिया गया जबकि बाकी आवेदकों को और कागजात उपलब्ध कराने के लिए कहा गया ताकि उनके दावों का निपटारा किया जा सके।

सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार चाहकर भी सहारा समूह की कंपनियों के मामले में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि हर चीज की निगरानी उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है। सहारा रिफंड को लेकर पूछे गए सवाल पर सीतारमण ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार तो हाथ जोड़कर खड़ी है कि आइए सारे कागजात लाइए और अपने पैसे ले जाइए। लेकिन कोई आ नहीं रहा है। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग बाहर जाकर ये ना कहें कि सरकार पैसा नहीं दे रही है। सरकार तो पूरी तरह से तैयार है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रही है। सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सीतारमण ने यह भी कहा कि सहारा समूह के पूरे मामलों की निगरानी उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है और सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है। उन्होंने कहा, ''यह सच है कि केवल छोटे निवेशक ही रिफंड का दावा करने के लिए आगे आए हैं। एसएफआईओ पूरे मामले की जांच कर रहा है। यह भी देख रहा है कि सभी निवेशक रिफंड का दावा करने के लिए आगे क्यों नहीं आए और वे कहां हैं।'

प्रमुख समाचार

बांग्लादेश पर केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी, हम उसके साथ

कोलकाता। शेख हसीना के बांग्लादेश की पीएम पद से इस्तीफा देने और वहां अंतरिम सरकार बनाने की खबर पर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बंगाल के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करता हूं। किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि यह दो देशों के बीच का मामला है, केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम उसका समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सरकार इस मुद्दे पर निर्णय लेगी कि इस मुद्दे पर कैसे संपर्क किया जाए और सभी राजनीतिक दलों के नेताओं से अपील की जाती है कि वे भड़काऊ टिप्पणियां करने से बचें जो बंगाल या देश में शांति को बाधित कर सकती हैं। ममता ने कहा कि कुछ भाजपा नेता पहले ही इस पर टिप्पणी कर चुके हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा कि बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से हो रहे विरोध प्रदर्शनों में कई लोगों की मौत हो गई। हम मीडिया से सुन रहे हैं कि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत आई हैं क्योंकि उनका भी मानना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश सुरक्षित है।

1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू प. बंगाल आ रहे हैं

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि हसीना के बयान के परिणामस्वरूप 1 करोड़ शरणार्थी बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल आएंगे। न सिर्फ भारत बल्कि बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरनाक है। शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में अशांति को लेकर खुलकर बात की. बांग्लादेश में हिंदुओं की अंधाधुंध हत्याएं हो रही हैं। उन्हें भारत में शरण दी जाएगी। इसको लेकर उन्होंने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से गुहार लगायी। शुभेंदु का अनुरोध है कि राज्य के मुख्यमंत्री इस मामले पर केंद्र सरकार से बात करें। शुभेंदु ने यह भी आशंका जताई कि अगर बांग्लादेश में ऐसी ही अशांति जारी रही तो शेख हसीना का देश जमात के हाथों में चला जाएगा। शुभेंदु अधिकारी विधानसभा से बाहर निकले और पत्रकारों से मुखातिब हुए। बांग्लादेश को लेकर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से एक करोड़ शरणार्थी पश्चिम बंगाल आएंगे। रंगपुर के पार्षद हराधन नायक की हत्या कर दी गई। सिराजगंज में 13 पुलिसकर्मी मारे गये. इनमें से 9 हिंदू हैं।

बांग्लादेश में भीड़ ने हिंदू मंदिरों पर किया हमला

ढाका। बांग्लादेश की राजधानी में सोमवार को उपद्रवी भीड़ ने एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की और देशभर में चार हिंदू मंदिरों को मामूली क्षति पहुंचाई। प्रत्यक्षदर्शियों और समुदाय के नेताओं ने यह जानकारी दी। हिंदू-बौद्ध-ईसाई एकता परिषद की नेता काजोल देबनाथ ने कहा कि उन्हें खबर मिली है कि देशभर में कम से कम चार हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने बताया, ये मामूली क्षति है। हालांकि, प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से इस्तीफा देने के बाद उत्पन्न तनावपूर्ण स्थिति को लेकर हिंदू समुदाय के कुछ नेता चिंतित हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बांग्लादेश की राजधानी के धानमंडी इलाके में स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र (आईजीसीसी) और बंगबंधु स्मारक संग्रहालय को एक उपद्रवी भीड़ ने सोमवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। ढाका ट्रिब्यून अखबार की खबर के अनुसार, सोमवार अपराह्न प्रदर्शनकारियों ने ढाका में कई प्रमुख स्थानों पर आगजनी की, जिसमें धानमंडी 32 स्थित बंगबंधु भवन भी शामिल है, जिसे बंगबंधु स्मारक संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। यह संग्रहालय हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को समर्पित है, जिनकी 1975 में राष्ट्रपति रहने के दौरान हत्या कर दी गई थी। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है.

पहले राज्यसभा में आएगा वक्फ अधिनियम में संशोधन विधेयक

नई दिल्ली। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के लिए एक विधेयक, जिससे वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने की उम्मीद है, पहले राज्यसभा में पेश किए जाने की संभावना है। समाचार एजेंसी एएनआई को सूत्रों ने बताया कि सरकार एक सप्ताह के भीतर इन संशोधनों को पेश करने के लिए आगे बढ़ सकती है। संसद का बजट सत्र 12 अगस्त को समाप्त होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक, सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन लाने से पहले सुधार लाने के लिए सुझाव जुटाने के लिए विभिन्न मुस्लिम बुद्धिजीवियों और संगठनों से परामर्श किया। कुल 32-40 संशोधनों पर विचार किया जा रहा है। राज्यसभा में एनडीए के लिए राह आसान नहीं है। इसलिए इसे पहले यहां लाया जा सकता है। वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद, इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया जिसने वक्फ बोर्डों को अधिक शक्तियां प्रदान कीं। 2013 में, संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के लिए वक्फ बोर्ड को दूरगामी शक्तियां देने के लिए इस अधिनियम में और संशोधन किया गया। सूत्रों के मुताबिक प्रस्तावित संशोधनों से वक्फ बोर्ड के लिए अपनी संपत्ति का पंजीकरण जिला कलेक्टर कार्यालय में कराना अनिवार्य हो सकता है, ताकि संपत्ति का मूल्यांकन किया जा सके.

राजस्थान में विपक्ष के विधायकों के साथ पक्षपात

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित पार्टी के अनेक नेताओं ने विधायक मुकेश भाकर को विधानसभा से निलंबित किए जाने की आलोचना की है। गहलोत ने आरोप लगाया है कि विधानसभा में विपक्ष के विधायकों के साथ 'अलोकतांत्रिक व पक्षपातपूर्ण' व्यवहार किया जा रहा है जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी वकीलों की नियुक्ति से जुड़े एक मुद्दे को लेकर हुए हंगामे व नारेबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मुकेश भाकर को सदन से निलंबित करने की घोषणा की। बाद में भाकर को सदन से निकालने के लिए आए मार्शलों व कांग्रेस विधायकों में धक्का मुक्की हुई। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने 'एक्स' पर लिखा, पहले विधानसभा में कांग्रेस विधायक मुकेश भाकरका निलंबन तथा जबरन निष्कासन फिर मार्शलों द्वारा वरिष्ठ विधायक हरिमोहन शर्मा को जमीन पर गिराना व विधायक अनिता जाटव से बदसलूकी कर उनकी चूड़ियां तक तोड़ देने की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं।

सरकार के खिलाफ विपक्ष का आक्रामण जारी, भाजपा का विकसित भारत पर जोर

अंकित सिंह

विपक्ष और सत्तारूढ़ दलों के बीच एक सप्ताह तक चली गहन बहस के बाद, एजेंडे में कई प्रमुख विधेयकों के साथ संसद का बजट सत्र आज फिर से शुरू हुआ। लोकसभा ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों को पारित किया। भूपेन्द्र यादव ने लोकसभा में मोरों की मौत पर सवाल का जवाब दिया। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने बांग्लादेश के घटनाक्रम से जुड़ा विषय लोकसभा में उठाने की कोशिश की। तेलक्षेत्र विनियमन एवं विकास संशोधन विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया। वहीं, आज विपक्ष ने सरकार पर गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा से बचने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बार फिर से विपक्ष को आज खूब सुनाया।

लोकसभा की कार्यवाही

नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाए जाने के पांच साल पूरा होने के मौके पर सोमवार को सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि यह कदम देश के लोकतंत्र और जम्मू-कश्मीर के लिए ठीक नहीं था। इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने प्रतिवाद किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए यह कदम उठाया था।

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जे पी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार जीडीपी का ढाई प्रतिशत बजट स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटित करने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रही है और उसने पिछले दस साल में स्वास्थ्य बजट आवंटन में 164 प्रतिशत की वृद्धि की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने पूरी ईमानदारी, पूरी ताकत के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है और दुनिया ने माना है कि भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में एक उदाहरण बन गया है। दुनिया के सारे लोग आयुष्मान भारत के मॉडल का अध्ययन कर रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि 'गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय' (एसएफआईओ) सहारा समूह की कंपनियों से संबंधित मामले की विस्तृत जांच कर रहा है और इसकी रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए सीतारमण ने यह भी कहा कि सहारा समूह के पूरे मामलों की निगरानी उच्चतम न्यायालय द्वारा की जा रही है और सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की मुद्रा ऋण श्रेणी से जुड़ी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) घटकर 3.4 प्रतिशत रह गयी है। उन्होंने प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा में एक पूरक प्रश्न के उत्तर में कहा कि यह 2020-21 में 4.77 प्रतिशत, 2019-20 में 4.89 प्रतिशत और 2018-19 में 3.76 प्रतिशत रहा।

विपक्षी दलों ने मत्स्य, पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए बजटीय आवंटन को अपर्याप्त करार देते हुए सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार को पशुपालकों, मत्स्यपालकों और डेयरी उत्पादकों के विकास के लिए बजट में बढ़ोतरी करनी चाहिए। दूसरी तरफ, भारतीय जनता पार्टी ने इस क्षेत्र में हुए विकास और सरकारी कदमों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दुग्ध उत्पादन, मत्स्य पालन तथा अन्य कई क्षेत्रों में देश ने खूब तरक्की की है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सयानी घोष ने कहा कि इस सरकार की स्थिति यह है कि पिछले 10 साल के दौरान हर दिन औसतन 30 किसानों ने आत्महत्या की है। घोष ने कटाक्ष करते हुए कहा, ''ये (भाजपा) गौरक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन आज चारा का संकट है। सरकार ने खुद माना है कि देश में चारा का संकट है।'' भाजपा सदस्य दुष्यंत सिंह ने कहा कि इस सरकार में किसानों को समृद्ध बनाने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि पशुपालन का गरीबी उन्मूलन में बड़ा योगदान है। सिंह का कहना था कि दुग्ध उत्पादन में वार्षिक छह प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

राज्यसभा की कार्यवाही

कांग्रेस को किसान विरोधी करार देते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को राजनीतिक दलों से अपील की कि वे किसानों को वोट बैंक मानना बंद करें तथा उनके साथ इंसान की तरह व्यवहार करें। उच्च सदन में कृषि मंत्रालय के कामकाज पर हुई चर्चा पर अधूरे रह गये अपने जवाब को आगे बढ़ाते हुए कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से न केवल छोटे एवं सीमांत किसान सशक्त हुए बल्कि उनका सम्मान भी बढ़ा है।

सरकार पर गृह एवं रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए विपक्ष ने सोमवार को राज्यसभा में दावा किया कि बड़ी-बड़ी घोषणाओं पर काम कुछ भी नहीं हुआ है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के कामकाज पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि वैसे तो सभी मंत्रालय महत्वपूर्ण हैं लेकिन इस मंत्रालय का संबंध देश की आने वाली पीढ़ियों से है। सरकार ने सोमवार को कहा कि विकसित भारत कोई परियोजना नहीं है, बल्कि एक विजन दस्तावेज है, जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की रूपरेखा रेखांकित करता है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा, ''यह वास्तव में कोई परियोजना नहीं है। यह एक विजन दस्तावेज है, जो तैयार किया जा रहा है...चूंकि विकसित भारत कोई परियोजना नहीं है, इसलिए राज्यों को वित्तीय सहायता देने का प्रावधान नहीं है।''

खेल, कला और व्यावसायिक कौशल में दक्ष बने विद्यार्थी : खाद्य मंत्री

■ नवागढ़ महाविद्यालय के कार्यक्रम में हुए शामिल

बेमेतरा। खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने आज बेमेतरा जिलें के नवागढ़ विकासखण्ड के शासकीय कोदूराम दलित महाविद्यालय के दीक्षारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। महाविद्यालय के नवप्रवेशित विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के संबंध में जानकारी दी गई । इस दौरान खाद्य मंत्री ने परिसर में पौधारोपण भी किया।

मंत्री श्री बघेल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य, प्रावधान, विशेषता और विभिन्न प्रकार के संकायों की जानकारी दी गई। शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों द्वारा चयन किये जाने वाले विषय जेनेरिक-इलेक्टिव का समूह तथा बैल्यू एडिशन कोर्स के समूह की व्याख्या किया। विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए एक समग्र और बहुविषयक दृष्टिकोण पर अधिक जोर देना है, ताकि विद्यार्थी विषयों के साथ-साथ खेल, कला और व्यावसायिक कौशल में दक्ष हो सकें। शिक्षा नीति के तहत विद्यार्थियों को क्रेडिट

आधारित कोर्सेस, सतत् आंतरिक मूल्यांकन एवं अंत सेमेस्टर परीक्षा से संबंधित प्रावधानों के बारे में समझाया गया है। विद्यार्थियों अथवा पालकों की शंकाओं का भी समाधान किया गया। इस अवसर पर नगर पंचायत नवागढ़ के अध्यक्ष श्रीमती मंजूलता रात्रे, नगर पार्षद श्री जाहिद बैग, शासकीय के.आर.डी. महाविद्याालय के प्राचार्य श्रीमती एम बंजारा और महाविद्यालय के परिवार के सदस्यगण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

खाद्य मंत्री ने हितग्राहियों को किया राशनकार्ड का वितरण

बेमेतरा। खाद्य मंत्री श्री दयाल दास बघेल ने आज बेमेतरा जिले के नगर पंचायत नवागढ में नगरीय प्रशासन विभाग के द्वारा आयोजित जनसमस्या निवारण पखवाड़ा शिविर का अवलोकन किया और हितग्राहियों से चर्चा करके राशनकार्ड वितरण, उचित मूल्य दुकान के माध्यम से खाद्यान की उपलब्धता एवं अन्य समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए शिविर का आयोजन किया गया है, जिनका राशनकार्ड नहीं बना है। वे 15 अगस्त 2024 तक नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। हितग्राही द्वारा खाद्य विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड करके नवीनीकरण का कार्य किया जा सकता है। हितग्राही उचित मूल्य दुकान में भी जाकर ऑनलाईन के माध्यम से अपने राशनकार्ड नवीनीकरण और ई-केवायसी का कार्य करवा सकतें है।

मंत्री श्री बघेल ने कहा कि ई-केवायसी के लिए प्रत्येक हितग्राही का बायोमेट्रिक अद्यतन होना चाहिए जिन सदस्यों का बाल आधार बना है उन्हें पहले आधार सेवा केंद्र से अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना होगा। इसके पश्चात् उचित मूल्य दुकान के ई-पॉस मशीन से ई-केवायसी करा सकते हैं। विदित हो कि राशनकार्ड में ई-केवायसी और नवीनीकरण की सुविधा निःशुल्क है। शिविर में आवेदन कर सकते हैं।

आधी रात हाथियों ने गांव में मचाया उत्पात, सात घरों में की तोड़फोड़

कोरबा। कोरबा जिले के कटघोरा वन मंडल में दो दंतैल हाथी का आतंक देखने को मिला। आधी रात गांव में घुसकर उत्पात मचाने लगे। इस घटना के बाद गांव में हड़कप मच गया। बीती रात पसान के समीप एक गांव में दो हाथी घुस गए और आतंक मचाने लगे जहां इस घटना के बाद गांव में हड़कम मच गया और कई ग्रामीण घर से भाग कर किसी तरह अपनी जान बचाये।

दोनों दंतैल हाथी ने एक के बाद एक साथ घरों को नुकसान पहुंचा। घर पर रख कई लोगों के अनाज को भी खा गया। ग्रामीण हाथी की चिंघाड़ सुनकर एक दूसरे के घर पर छुपे हुए थे। हाथी मकान क्षतिग्रस्त करने के बाद खेतों में पहुंचा जहां काफी फसलों को भी बर्बाद कर दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचे और किसी तरह

हाथी को रेस्क्यू कर जंगल की ओर खदेड़ा। वही गांव में आसपास मुनादी कराई गई। ग्रामीणों को जंगल से जाने के लिए रोका गया।दोनों हाथियों ने तोड़फोड़ डाला। कई एकड़ जमीन पर खड़ी फसल को नष्ट कर दिया।

ग्रामीणों की माने तो झुंड से बिछड़ कर यह दोनों हाथी पिछले कुछ दिनों से इस इलाके में विचरण कर रहे हैं जिस भय बना हुआ है और रातजग्गा करने को मजबूर है। हाथी प्रभावित होने के कारण लोग खेतों में काम करने जाने से भी डर रहे हैं। वहीं इस मामले में पसान वन वन परिक्षेत्र के रेंजर रेंजर रामनिवास को दी गई। उन्होंने वन विभाग की टीम के साथ गांव पहुंचकर हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा। बताया जा रहा है कि हाथी अभी भी गांव से 2 किलोमीटर दूर कोसाबाडी जंगल में विचरण कर रहे हैं जिसके कारण आसपास के ग्रामीण दहशत में है।

वन विभाग की माने तो घरों को हाथियों के द्वारा तोड़ा गया है इसका सर्वे किया जा रहा है वहीं फसलों का जो नुकसान हुआ है उसे आकलन कर रिपोर्ट तैयार की जारी है जहां आगे की कार्यवाही की जाएगी।

मुक्तिधाम के जमीन पर दबंगों का कब्जा ग्रामीणों ने एनएच पर किया चक्काजाम

प्रशासन ने 15 दिन के भीतर कार्रवाई का दिया आश्वासन

गरियाबंद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले के अंतर्गत मैनपुर में मुक्तिधाम के लिए आरक्षित लगभग 6 एकड़ जमीन पर दबंगों ने सालों से कब्जा कर रखा है। ऐसे में अस्थाई रूप से बनाया गया मुक्तिधाम हर साल बारिश के मौसम में तब्दील हो जाता है। यही हाल हरदीभाठा मुक्तिधाम का भी है। ऐसे में दोनों मुक्तिधाम के लिए आज सुबह ग्रामिणों ने मैनपुर अस्पताल के सामने नेशनल हाइवे 130 सी पर चक्काजाम कर दिया। प्रदर्शन के चलते हाइवे पर लंबे समय तक आवाजाही ठप रही। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को 15 दिन के भीतर अवैध कब्जा हटाने का आश्वासन देकर मामले को शांत कराया।

जानकारी के अनुसार, अवैध कब्जे के चलते 12 साल पहले जयंती नगर के स्कूल के करीब अस्थाई मुक्तिधाम बना गया। लेकिन देख रेख के अभाव में यहा भी गंदगी पसर गया। हर साल बारिश के मौसम में पूरा मुक्तिधाम दल दल में तब्दील हो जाता है। सालों से हो रही परेशानी के चलते स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने आज दुकाने बंद कर चक्काजाम का समर्थन किया।

ग्रामीणों का आरोप है कि चिन्हांकित मुक्तिधाम के विकास के लिए पंचायत मद में रूपए भी आए। मैनपुर जनपद को मुक्तिधाम के विकास के लिए 15 दिसंबर 20 12 में 6 184 लाख रूपए की मंजूरी मिली। इसके बाद भी वह इन पैसों को खर्च नहीं कर पाई।

वहीं इस मामले में मनरेगा के पीओ रमेश कंवर को फोन कर वजह जानने की कोशिश की गई, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। नए पदस्थ सीईओ डी एस नागवंशी पुराने फाइलों के बारे में ज्यादा कुछ जानते नही थे, लिहाजा उन्होंने कहा कि जांच करवाया जाएगा कि काम क्यों नहीं हुआ।

दिव्यांग दंपती को नहीं मिल रहा सरकारी योजनाओं का लाभ, जीवन-यापन में परेशानी

बीजापुर। लाख सरकारी दावों के बीच बीजापुर के ग्राम पंचायत तोयनार से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने सरकार के सिस्टम की पोल खोल दी है। सरकार और सरकार के सिस्टम में बैठे लोग भले ही कहते हैं कि हमारी हर योजना का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही है, लेकिन यह तस्वीर बताने के लिए काफी है। गरीबी निराशा, दुख, दर्द लाती है। बच्चे शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते। परिवार आर्थिक तंगी से जीवन जीने को मजबूर हो जाता है।

एक तरफ सरकार की ओर से गरीब, असहाय लोगों के उत्थान के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है पर जिम्मेदारों की अनदेखी के कारण कई असहाय परिवार गरीबी का दंश झेलने को मजबूर हैं। अमीरों को तो सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल जाता है, किंतु गरीब अपने हक के लिए जिम्मेदारों की अनदेखी से लाचार रहता है। मजबूरन गरीब व पात्र व्यक्ति तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हो जाता है। इसी प्रकार का एक मामला बीजापुर विकासखंड के तोयनार के मुर्रा पारा से आया है, जहां के 49 साल के सुक्कू तांती जन्म से ही विकलांग है। वहीं उनकी पत्नी 34 साल की सरिता ताती भी बचपन से ही गूंगी बहरी है।

दोनों पति पत्नी अपने दो बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। दोनों विकलांग होने के कारण कोई भी कार्य नहीं कर पाते हैं। स्थिति ऐसी है कि कभी कभी एक समय परिवार को भूखा भी सोना पड़ता जाता है।, इन्हें अब तक सरकार से न कोई राहत राशि मिली न ही किसी योजना का लाभ मिला है। मामले की हकीकत जानने मीडिया की टीम

ग्राम पंचायत तोयनार के मुर्रा पारा पहुंची और पीड़ित एंव स्थानीय ग्रामीणों से की चर्चा।

रोड में काम करने का अब तक नहीं मिला पैसाः सुक्खू

सुक्खू ताती ने बताया कि मेरे पास सिर्फ राशनकार्ड है, जिसमें मेरे को चावल ही मिलता है, लेकिन सब्जी व अन्य सामग्री के लिए घर में मुर्गी पालना करते हैं। मैं और मेरी पत्नी दो महीना पहले मेरे घर के सामने जो रोड बना है, उसमें सात से आठ दिन काम भी किया, लेकिन पैसा अभी तक नहीं मिला। जीवन-यापन करने में बहुत परेशानियां आती है। वहीं ग्रामीणों ने भी कहा कि सिर्फ इन्हें सोसायटी से राशन मिलता है और शासन की योजनाओं का लाभ अभी तक नहीं मिला। हम लोगों ने भी कई बार कहा, लेकिन इन्होंने डर से लाभ लेने से इंकार कर दिया। डर इस बात का है कि कहीं सरकार का लाभ लेने के बाद वापस सरकार को पैसा न पटाना पड़े। इस बात का डर सुक्खू ताती को बना हुआ है।

कोरिया जिला परिवहन विभाग ऑफिस में आगजनी

कोरिया। कोरिया जिले के रामपुर स्थित जिला परिवहन विभाग में आगजनी की घटना हो गई। आगजनी में परिवहन विभाग कोरिया के परिवहन संबंधित दस्तावजों को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि सुबह से ही कार्यालय के अंदर से धुंआ उठ रहा था। जब स्थानीय लोगों ने पास जाकर देखा तो अंदर आग लगने की जानकारी हुई।इसके बाद तत्काल अधिकारियों को इस बात की सूचना दी गई।

आगजनी की सूचना परिवहन विभाग के अधिकारियों को जैसे ही मिली सभी तत्काल दफ्तर में पहुंचे।जहां सभी ने निरीक्षण के बाद दमकल विभाग को सूचित किया। 10 मिनट के अंदर ही दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।आगजनी के मामले में परिवहन विभाग के सहायक जिला अधीक्षक संचित मिंज का कहना है कि दिनेश राज नामक व्यक्ति ने चौकीदार के साथ-साथ फायर ब्रिगेड को सूचना दी कि परिवहन विभाग के दफ्तर में आग लग गई है। अंदर से धुआं निकल रहा है। जिसकी बाद फायर ब्रिगेड की टीम समय रहते पहुंच गई।

सहायक जिला अधीक्षक परिवहन विभाग संचित मिंज ने कहा वर्तमान समय में जो जानकारी मिली है वो ये है कि आगजनी शॉर्ट सर्किट के कारण हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं ऑफिस में जो पुरानी एसी लगी थी उससे हादसा हुआ है।बहरहाल सफाई का काम जारी है,चीजें बाद में स्पष्ट हो पाएंगी।

आगजनी की घटना को देखने के बाद शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट आग का कारण माना जा रहा है।इस आगजनी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जलकर राख में तब्दील हो गए।वहीं परिवहन विभाग के अंदर कई मूल दस्तावेजों को भी नुकसान पहुंचा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

नक्सल प्रभावित सुकमा की बेटी माया कश्यप बनीं डॉक्टर

सुकमा। सुकमा यह नाम सुनते ही जेहन में नक्सलवाद की तस्वीरें घूमने लगती है। कई खूनी संहार सुकमा ने देखा है। लेकिन बदलते इस समय मे सुकमा अब नक्सल ही नहीं अपनी प्रतिभाओं के लिए जाना जाने लगा है। चाहे सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सहदेव हो या दोरनापाल की बेटी डॉक्टर माया। दरअसल, बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इलाज के अभाव से कई ग्रामीणों की मृत्यु हो जाती है। बाहरी डॉक्टर अपनी सेवा बस्तर में नहीं देना चाहते इसके पीछे का कारण भी नक्सल भय है। लेकिन नक्सल प्रभावित जिले की माया कश्यप अब अपनी डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर अपनी सेवा सुकमा जिला अस्पताल में देगी जिससे अपनी सपनों को पूरा करते हुए माया कश्यप डॉक्टर बनकर अपने ही जिलेवासियों की सेवा करेगी। राज्य शासन ने सुकमा जिले को दस डाक्टरों को नियुक्ति दी है। जिसमें डॉक्टर माया कश्यप का भी नाम शामिल है। माया अपने नाम को देख खुशी जाहिर करते हुए अपने सपने के बारे में बताया। बचपन से ही कई मुश्किल हालातों का सामना करते हुए अपने सपने को पूरा किया।

जंगल में लगाए जाल में फंसा तेंदुआ, वन विभाग में हड़कंप

गरियाबंद। उदंती सीतानदी टाइगर रिजर्व

क्षेत्र से एक बड़ी खबर सामने आई है। वन प्राणियों के शिकार करने के लिए जंगल में लगाए गए जाल में तेंदुआ फंस गया। इसकी जानकारी लगते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग ड्रोन कैमरे के माध्यम से जाल में फंसे तेंदुआ की निगरानी कर रहा था। वन अमला तेंदुआ को जल से छुड़ाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा था, तभी 11:30 बजे के आसपास तेंदुआ स्वयं झटका मारकर जाल से निकलकर पहाड़ी के तरफ निकल गया। इस घटना की पुष्टि करते हुए उदंती टाइगर रिजर्व की उपनिदेशक वरुण जैन ने बताया कि घायल तेंदुए की निगरानी की जा रही है।

अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट में छग ने ट्रॉफी पर किया कब्जा

भिलाई। आगरा में 23 जुलाई से अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था।छत्तीसगढ़ की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए महाराष्ट्र की टीम को हराया और ट्रॉफी को अपने नाम किया। अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट में देश के आठ राज्य तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुच्चेरी, गोवा और छत्तीसगढ़ ने भाग लिया। सभी को पछाड़कर छत्तीसगढ़ की टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की। कोच संतोष भारद्वाज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की टीम ने अंडर-19 क्रिकेट टूर्नामेंट महाराष्ट्र को हराकर जीत हासिल की है। उन्होंने सरकार से खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर सोचने की मांग की। खिलाड़ियों को अच्छा डाइट और अच्छे क्रिकेट किट उपबल्ध कराने की मांग की। पूर्व वेल्डरमैन अरविंद राय ने कहा कि छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करने वाले इन बच्चों को मैं बधाई देता हूं। इन बच्चों के पास खेलने के लिए सही ढंग का एक ग्राउंड भी नहीं था। खिलाड़ियों ने बताया कि कोच संतोष भारद्वाज ने काफी मेहनत की। इसी की बदौलत हमारी टीम ने छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया।

खेत में काम करने गए बुजुर्ग की डूबने से हुई मौत

जगदलपुर। जगदलपुर के परपा थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगरीगुड़ा में रहने वाला बुजुर्ग अपने खेत में काम करने के दौरान पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी परिजनों को दो घंटे के बाद लगी। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि डोंगरीगुड़ा निवासी सुखदास गोयल पिता स्व. गोजु गोयल 50 वर्ष रोजाना की तरह आज सुबह भी अपने खेत मे काम करने के लिए गया हुआ था, चुकी बरसात के चलते खेत मे पानी का भराव ज्यादा होने के कारण उसे रास्ता समझ नही आया और अपने ही खेत के पानी मे डूबने से उसकी मौत हो गई, चुकी बुजुर्ग अकेले खेत मे काम कर रहा था, इसलिए उसे बचाने के लिए उस समय कोई भी नही था। दो घंटे के बाद बुजुर्ग का बेटा समन गोयल खेत मे काम करने के लिए जब आया तो उसने पानी मे अपने पिता को डूबा देख, उसे बाहर निकालने के साथ ही पुलिस और परिजनों को सूचना दिए, लेकिन जब तक बुजुर्ग को बाहर निकाला गया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सोमवार की सुबह शव का पीएम के लिए मेकाज लाया गया।

पुरानी रंजिश को लेकर युवक पर चाकू से हमला

बिलासपुर। बिलासपुर में चाकूबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है, पुरानी रंजिश को लेकर आपसी विवाद के दौरान चाकू मारकर युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला सरकंडा थाना के तहत चिंगराजपारा संतोषी चौक का है, जहां पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी युवक ने नरेंद्र चंद्राकार नाम के युवक से विवाद करने लगा। इस दौरान दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई और फिर आरोपी युवक वहां से निकल गया। थोड़ी देर बाद फिर आरोपी अपने तीन साथियों के साथ मौके पर चाकू लेकर पहुंचा और गुस्से में नरेन्द्र के पीठ में चाकू घोंप दिया, जिससे मौके पर ही नरेंद्र घायल होकर गिर पड़ा, घटना के बाद सरकंडा पुलिस को मामले की सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस स्थानीय लोगों की मदद से नरेंद्र चंद्राकार को सिम्स अस्पताल लेकर पहुंची जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, इधर सरकंडा पुलिस ने मामले में मुख्य आरोपी समेत उसके साथियों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई में जुटी है।

सिंचाई विभाग और ठेकेदार की लापरवाही से हादसा

■ नहाने के दौरान खोरसी नाले में बहा युवक, 6 घंटे बाद भी नहीं मिला

बलौदाबाजार। यूपी से छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार घूमने आया युवक नहाते समय खोरसी नाले के तेज बहाव में बह गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और नगर सेना की टीम मौके पर पहुंची है। युवक की खोजबीन जारी है। 6 घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद से परिजन परेशान हैं।

जानकारी के मुताबिक, उत्तरप्रदेश से अपने परिचित के साथ कुलदीप प्रजापति उम्र 17 वर्ष बलौदाबाजार घूमने आया था। इस दौरान नहाते समय खोरसी नाला में निर्माणाधीन एनीकट के पास पानी के तेज बहाव में बह गया। 6 घंटे बीत जाने के बाद भी युवक का कोई पता नहीं चला है। नगर

सेना की दस सदस्यीय टीम मौके पर पहुंचकर केवल कांटा डालकर खानापूर्ति करते नजर आ रही है। नगर सेना की टीम का कहना है कि पत्थर होने की वजह से बोट नहीं चल सकता है। ऐसे में गोताखोर की आवश्यकता है।

बता दें कि जहां यह एनीकट का निर्माण हो रहा है वहां पर न ही कोई सांकेतिक बोर्ड लगा है और न ही सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। यह सिचाई विभाग और ठेकेदार की लापरवाही को दर्शाता है। इसकी वजह से आज एक युवक पानी के तेज बहाव में बह गया है।

कलेक्टर दीपक सोनी ने बाढ़ को देखते हुए लोगों से लगातार अपील कर रहे थे कि नदी नाले के पास न जाएं। साथ ही बाढ़ राहत दल को तैयार रहने के निर्देश दिए थे पर आज की स्थिति देख लग रहा कि नगर सेना के पास गोताखोर नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है। वहीं सुबह से युवक के खोजबीन में लगे नगर सेना की टीम को न ही नाश्ता मिला और न ही खाना, जिसके चलते नगर सेना की टीम वापस चली गई। नगर सेना के धनीराम दाण्डेकर ने बताया कि सुबह से आए थे। यहां खाने की व्यवस्था नहीं की गई। इस वजह से हम लोग वापस जा रहे हैं।

गंभीर बीमारी से जिंदगी की जंग लड़ रही बेटी

मुंगेली। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक गंभीर बीमारी से ग्रसित 16 वर्षीय बेटी के इलाज के लिए परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित बेटी के माता-पिता ने 4 साल से बेटी के इलाज में अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी, लेकिन उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। अब डॉक्टरों ने उन्हें बीमार बेटी को तमिल नाडु के वेल्लूर में इलाज कराने की सलाह दी है। इसके लिए बेबस गरीब माता पिता की निगाहें अब प्रशासन की तरफ है। दरअसल, मुंगेली जिले के एक छोटे से गांव केसतरा कि निवासी राजेश यादव का परिवार हंसते खेलते जीवन गुजर रहा था। लेकिन 4 साल पहले 8 दिसम्बर 2020 को अचानक उनकी बेटी भावना ऐसे बीमार हुई कि वह कभी सामान्य नहीं हो पाई। भावना 6वीं कक्षा में थी जब उसकी तबीयत बिगड़ी।

शिक्षकों की कमी से नाराज छात्रों ने नेशनल हाईवे किया जाम

कांकेर। कांकेर जिले में स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय के छात्र- छात्राएं आज शिक्षकों की कमी से नाराज होकर नेशनल हाइवे सड़क में उतर कर प्रदर्शन करने लगे। छात्र एक घंटे तक नारेबाजी करते रहे। विद्यालय के प्रिंसपल,

पुलिस और प्रशानिक अमले के समझाने के बाद भी छात्र मान नहीं रहे थे। एक घंटे के जाम से रायपुर से जगदलपुर और जगदलपुर से रायपुर की ओर आ रही गाड़ियों का जमावड़ा लग गया। पुलिस के द्वारा छात्रों के ऊपर मामला दर्ज करने की बात से छात्र और उग्र हो गए। पुलिस ने छात्रों को अंततः सड़क से उठा कर किनारे किया।

छात्र-छात्राओं ने बताया कि विद्यायल में शिक्षकों की भारी कमी है. प्राचार्य सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी में झण्डा फहराने आते है. कोई अधिकारी विधालय के निरीक्षण में नही आता है. कई बार हमने एडिशनल डारेक्टर को लिखित आवेदन देकर शिक्षको की कमी से अवगत कराया है लेकिन कोई सुनने वाला नही है. शिक्षको की कमी के कारण हमारा सिलेबस पूरा नही हो रहा है. इसीलिए आज सड़क में उतरना पड़ रहा है और हमे ही पुलिस दबाव बना रही है.

वहीं इस पूरे मामले में सहायक आयुक्त एलआर कुर्रे का कहना है कि, शिक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शिक्षकों को सोमवार को ज्वाइन करना था, लेकिन बच्चों ने उसके पहले ही आंदोलन शुरू कर दिया है। जल्द ही शिक्षक ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि अब तक शिक्षक ज्वाइन करने नहीं पहुंचे थे।

संक्षिप्त समाचार

कबीरधाम के भोरमदेव मंदिर में सीएम साय ने पूजा अर्चना की

कबीरधाम। 5 जुलाई को सावन माह का

तीसरा सोमवार था। सभी शिव मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। छत्तीसगढ़ के खजुराहों कहे जाने वाले भोरमदेव के शिव मंदिर में भी कई आयोजन हुए। सोमवार को राज्य के सीएम विष्णु देव साय भोरमदेव मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे थे। खास बात यह है कि सीएम विष्णुदेव साय हेलीकॉप्टर से भोरमदेव मंदिर पहुंच कर पदयात्री कांवरियों का पुष्प वर्षा से स्वागत किया। सोमवार को दो हेलीकॉप्टर से भोरमदेव मंदिर परिसर के आसपास कांवरियों पर पुष्प वर्षा की गई। सीएम विष्णु देव साय व डिप्टी सीएम विजय शर्मा दोनों कबीरधाम पहुंचे थे। मुख्यमंत्री साय प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि के लिए मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना और अभिषेक किया। तय कार्यक्रम के मुताबिक, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सोमवार सुबह 7.05 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा पुलिस ग्राउंड रायपुर से प्रस्थान कर 7.35 बजे पीजी कॉलेज हेलीपेड कवर्धा पहुंचे। इसके बाद 7.35 बजे कार द्वारा प्रस्थान कर भोरमदेव पहुंचे। मुख्यमंत्री साय ने इसके बाद भोरमदेव मंदिर में पूजा-अर्चना की। इस बीच हेलिकाप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से राज्यपाल रमेन डेका ने की मुलाकात

रायपुर। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में राज्यपाल रमेन डेका ने मुलाकात की। इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह को राज्यपाल रमेन डेका ने पुष्पगुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस दौरान प्रथम महिला रानी डेका काकोटी भी उपस्थित थीं।

स्वास्थ्य मंत्री जायसवाल के प्रयास से सरगुजा संभाग को मिले 100 चिकित्सक

जशपुर। राज्य सरकार ने 535 संविदा एमबीबीएस चिकित्सकों की पदस्थापना की है। स्वास्थ्य मंत्री एवं मनेन्द्रगढ़ के स्थानीय विधायक श्री श्याम बिहारी जायसवाल के प्रयासों से इन चिकित्सकों में से 100 चिकित्सकों की पदस्थापना सरगुजा संभाग में की गयी है। इनमें से बलरामपुर में 19, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 16, जशपुर में 21, कोरिया में 6, सूरजपुर मे 6 तथा सरगुजा जिले में 32 चिकित्सकों की संविदा नियुक्ति की गयी है। इससे पहले भी स्वास्थ्य मंत्री के प्रयासों से क्षेत्र में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है। अब संभाग में 100 चिकित्सकों की नियुक्ति से सुदूर क्षेत्र के ग्रामीणों को भी त्वरित स्वास्थ्य उपचार का लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों की कमी दूर होने से लोगों को सहूलियत मिलेगी और बेहतर इलाज की सुविधा मिलेगी।

छत्तीसगढ़ के राहुल 15 अगस्त को माउंट कोज़िअस्को पर फहराएंगे तिरंगा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के प्रथम पर्वतारोही राहुल गुप्ता 'माउंटेन मैन' पर्वतारोहण क्षेत्र में नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहे है। 15 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोज़िअस्को में तिरंगा फहराएंगे। माउंटेन मेन राहुल गुप्ता ने आज खेल मंत्री से मुलाकात कर आगामी अभियान के लिए आशीर्वाद लिया। अगले महीने 8 अगस्त को रायपुर से इस अभियान के लिए निकलेंगे। राहुल, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे ऊंची चोटी माउंट कोज़िअस्को (7,310 फिट) की ऊंची चोटी पर चढ़ाई करेंगे। जो कि महाद्वीपों के पहाड़ों की ऊंचाई की रैंकिंग में सातवां व सबसे छोटी चोटी है। राहुल गुप्ता आगामी 15 अगस्त को पीक फतह करेंगे। इस दौरान लगभग माइनस (अधिकतम - 10 डिग्री) तापमान तक मे ट्रेकिंग के द्वारा लगभग 23 किलोमीटर दूरी तय करके पूरा करेंगे।16

संपर्क क्रांति ट्रेन से हरियाणा की शराब जब्त

रायपुर। आबकारी टीम रायपुर की टीम ने संपर्क क्रांति ट्रेन से हरियाणा की शराब जब्त की है। शनिवार को मुखबिर से सूचना मिली कि रायपुर स्टेशन में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में रेलवे कोच के अटेंडर द्वारा अवैध शराब बेची जा रही है। आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, जेल से छूटकर आने के बाद दोहराया वही काम

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। आरोपी जेल से छूटने के बाद भी चाकू दिखाकर लोगों को डराने धमकाने और लूटने का प्रयास कर रहे हैं। आरोपी बलवा के प्रकरण से छूटने के बाद एक बार फिर गुंडागर्दी सामने आया है। मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। पूरा मामला रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र का है, जहां आदतन आरोपी खीरसिंधु नायक जेल से छूटने के बाद धारदार चाकू लेकर लोगों को डराते धमकाते धारदार चाकू के साथ रंगेहाथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी इस घटना से पहले 15 जुलाई को रायल पब्लिक स्कूल के पास अपने साथियों के साथ मिलकर एक व्यक्ति के साथ गाली गलौज कर मारपीट किये थे, जिस पर प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपियों के खिलाफ मारपीट और बलवा के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था। इसके बाद फिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।

नक्सलियों के उन्मूलन के लिये विष्णुदेव सरकार द्वारा उठाये गये कदम स्वागतेय

■ मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ी सुराज का स्थापना दिवस मना

रायपुर। मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ी सुराज का स्थापना दिवस विगत दिनों एक गरिमामय आयोजन के साथ मनाया गया। इस मौके पर - छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद और नई सरकार - विषय को लेकर परिचर्चा भी आयोजित की गई थी। जिसमें वक्ताओं ने नक्सलियों का उन्मूलन के लिये विष्णुदेव सरकार द्वारा उठाये गये कदम को स्वागत योग्य बताया।

मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ी सुराज के प्रधान संपादक शंकर पांडे ने पहले पत्रिका के प्रकाशन पर प्रकाश डाला। पश्चात विषय पर बोलते हुए कहा कि छत्तीसगढ में नई सरकार बनने के बाद नक्सली क्षेत्र बस्तर में सुरक्षाबल नक्सलियों के गढ़ अबूझमाड़ भी पहुंच सफलतापूर्वक मुठभेड़ कर चुका है। वर्ष 2024 में नक्सलियों के विरूद्ध प्रभावी रूप से नक्सल विरोधी अभियान संचालित किये जाने के परिणाम स्वरूप बस्तर रेंज के अंतर्गत अब तक कुल 142 नक्सलियों के शव मिले ,482 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया तो अभी तक 453 ने आत्मसमर्पण भी किया है। बस्तर रेंज में तैनात पुलिस एवं सुरक्षा बल ने क्षेत्र की जनता की जान- माल की रक्षा हेतु माओवादियों के विरूद्धप्रभावी रूप से कार्यवाही की जा रही है और आगे भी जारी रहेगी जिससे क्षेत्र की जनता को नक्सल गतिविधियों से मुक्ति मिलने के साथ- साथ बस्तर को एक नयी सकारात्मक पहचान मिलेगी।

नक्सली क्षेत्रों में जाकर, कुछ वारदातों की घटना स्थल पर जाकर, नक्सली प्रभावितों से कई बार चर्चा करने वाली वरिष्ठ पत्रकार प्रियंका कौशल ने परिचर्चा में हिस्सा लेते हुये कहा कि निश्चित ही विष्णुदेव सरकार बनने के बाद इतनी अधिक संख्या में नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराना, गिरफ्तारी और आत्म समर्पण सरकार की नक्सलियों के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का परिचायक है। वैसे राज्य सरकार इसके साथ ही बातचीत का रास्ता भी खुला रखा है, वहीं मूल धारा में नक्सली के लौटने पर उनके पुनर्वास के लिये और भी अच्छी योजना बना रही है, वैसे पूर्ववर्ती डॉ रमन सरकार ने भी नक्सली उन्मूलन में बड़े कदम उठाये थे।

पत्रकार तथा साहित्यकार विनोद कशिव का मानना था कि छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सली समस्या विरासत में मिली थी, अविभाजित मप्र के समय नक्सली बस्तर में सक्रिय हुये थे, अब तो यह नासूर बन चुके हैं, तेजी से विकास की और बढ़ते छग के लिये सबसे बड़े बाधक नक्सली ही है, स्कूल भवन, पंचायत भवन,सड़क, पुल-पुलिया को विस्फोट से उड़ा देना, सुरक्षाबलों सहित आम नागरिकों की हत्या, धन उगाही से नक्सलियों के मँसूबे स्पष्ट हैं? उनकी कोई आइडियोलाजी ही नहीं है,इस समस्या को कड़ाई से सुलझाने विष्णु देव सरकार की पहल सराहनीय है।

वरिष्ठ पत्रकार विशाल यादव का कहना था कि मप्र के समय से उपजी नक्सली समस्या को समाप्त करने छग राज्य बनने के बाद डॉ रमन सिंह तथा अब विष्णुदेव सरकार द्वारा उठाये गये कदम उल्लेखनीय कहे जा सकते हैं। छग में चहुमुखी विकास की बड़ी संभावनायें है और नक्सली समस्या के चलते बस्तर में कोई बड़ा उद्योग स्थापित नहीं हो सका है,वहाँ की बेरोज गारी की समस्या को नक्सली भुना रहे हैं, नक्सली उन्मूलन ही बस्तर की हर समस्या का हल है।

रविभवन व्यापारी संघ के पूर्व अध्यक्ष तथा छग चेम्बर ऑफ़ कॉमर्स के सक्रिय सदस्य जय नेभानी का कहना था कि बस्तर सहित नक्सली प्रभावित क्षेत्र में व्यापार जगत भी प्रभावित है, बस्तर में जो जड़ी बूटी, कंदमूल, प्राकृतिक दवाइयों का खजाना है, लोह अयस्क,अन्य खनिज हैं, उनका दोहन भी नहीं हो पा रहा है, नक्सलियों के आतंक के चलते व्यापारी वहाँ खुलकर व्यापार नहीं कर पाते हैं, छग सरकार के वर्तमान कार्य काल में नक्सली उन्मूलन हेतु उठाया गया कदम स्वागतेय है। निजी बैंक के आईटी मैनेजर राज कुमार बिसेन ने कहा कि नक्सली प्रभावित क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली भी उस मुकाम तक नहीं पहुंची हैं, जहाँ होनी थी, छग को नक्सलमुक्त होना ही चाहिये।

संभागायुक्त ने किया तीन शासकीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण

■ 25 से अधिक अनुपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस जारी करने दिए निर्देश

रायपुर। संभागायुक्त श्री महादेव कावरे आज सुबह राजधानी रायपुर स्थित तीन शासकीय कार्यालयों का निरीक्षण किया और निर्धारित समय 10 बजे कार्यालय से अनुपस्थित लगभग 25 अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। श्री कावरे आज सुबह कृषि विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय पहुंचे। कार्यालय में निर्धारित समय 10 बजे कोई अधिकारी कर्मचारी उपस्थित नही थे। कार्यालय के मेन गेट पर लगा ताला देख संभागायुक्त ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने संयुक्त संचालक से दूरभाष पर बात कर सभी अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। श्री कावरे ने इसके बाद नगर एवं निवेश विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय और सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय का भी निरीक्षण किया। इन दोनों कार्यालयों में भी अनुपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश संभागायुक्त ने दिए। उन्होंने सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्धारित समय सुबह 10 बजे कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान नगर एवं निवेश कार्यालय पहुंचे संभागायुक्त ने उपस्थित कर्मचारियों से लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत लंबित प्रकरणों की जानकारी मांगी। उपस्थित कर्मचारी द्वारा जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाने पर श्री कावरे ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का ऑनलाइन रिकार्ड रखने के साथ-साथ पंजी संधारण करने के निर्देश भी दिए। संभागायुक्त ने उपस्थित कर्मचारियों को निर्देशित किया कि कार्यालय में आने वाले नागरिकों को शासकीय योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ सरलता से दिलाने का प्रयास किया जाए। नागरिकों को अपने कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े। संभागायुक्त ने लंबित प्रकरणों का भी शासकीय नियम अनुसार त्वरित निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। संभागायुक्त ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम सहित शासकीय योजनाओं और उनके क्रियान्वयन के लिए निर्धारित समय सीमा की जानकारी कार्यालयों के बाहर समुचित स्थान पर प्रदर्शित करने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए।

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय शिव भक्त कावडियों पर पुष्प वर्षा करने के उपरांत कबीरधाम जिले के पी.जी.कालेज हेलीपेड पहुंचने पर जनप्रतिनिधियों, ग्रामीणों और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने आत्मीय स्वागत किया। मुख्यमंत्री कबीरधाम जिले के भोरमदेव में बाबा भोरमदेव और बूढ़ा महादेव में दर्शन व अभिषेक करेंगे।

रायपुर एम्स में कार्डियक पेशेंट्स को मिलेगी और ज्यादा सुविधा

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में नई कार्डियक कैथीटेराइजेशन प्रयोगशाला का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने रविवार को इस प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। एम्स रायपुर में अब तक सिर्फ एक कैथ लैब थी, जिससे हर हफ्ते लगभग 25 से 30 एंजियोग्राफी की जाती थी। एम्स में अत्याधुनिक सुविधा शुरू हो जाने से छत्तीसगढ़ के हार्ट पेशेंट को इसका काफी फायदा मिलेगा।

कार्डियक कैथीटेराइजेशन प्रयोगशाला से मिलेगा फायदा- अस्पताल द्वारा जारी बयान में कहा गया दूसरी लैब न केवल रोगी के प्रतीक्षा समय को कम करेगी, बल्कि समय पर और कुशल हृदय देखभाल प्रदान करने की अस्पताल की क्षमता को भी बढ़ाएगी। नई लैब डीएम (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन) कार्डियोलॉजी कार्यक्रम में मेडिकल छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण मैदान के रूप में भी काम करेगी, जो अत्यधिक कुशल हृदय रोग विशेषज्ञों की एक नई पीढ़ी को बढ़ावा देगी।

एम्स में नई कार्डियक कैथीटेराइजेशन प्रयोगशाला के

उद्घाटन के दौरान केंद्रीय आयुष और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने एम्स मेंआपातकालीन शिशु रोग विभाग, ट्रॉमा और आपातकालीन विभाग और आयुष विभाग सहित प्रमुख विभागों का भी दौरा किया। जाधव ने एम्स रायपुर के कार्यकारी निदेशक, डीन और चिकित्सा अधीक्षक के साथ बैठक भी की।

विधायक राजेश मूणत ने कांग्रेस पर कसा तंज

दक्षिण विधानसभा सीट उपचुनाव में भाजपा जीतेगी

रायपुर। छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। इस सीट में चुनाव को लेकर सत्ता दल और विपक्ष बयान दे रहे हैं। साथ ही अपने-अपने जीत के दावे भी कर रहे हैं। वहीं दक्षिण विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तेज तैयारी पर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कितने भी बड़े चेहरे मैदान में उतार लें, भाजपा का साधारण सा कार्यकर्ता जीतकर आएगा।

पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट में अभी चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई हैं। भाजपा संगठन और कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी हैं। पार्टी के कार्यकर्ता चौबीस घंटे आम जानता के टच में रहते

हैं, कार्यक्रमों के माध्यम से पार्टी की सक्रियता बनी रहती है। भाजपा जहां चुनाव लड़ती हैं, जिसको भी कमल छाप मिलेगा वो विजय प्राप्त करेगा। अभी हर बूथ पर घर-घर तिरंगा कार्यक्रम होने वाला है। 11 से 15 तक घर-घर तक जाकर जनता को जागरूक किया जाएगा। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये हैं कि राज्य के लोककल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनता को मिलना चाहिए। कांग्रेस कितने भी बड़े चेहरे मैदान में उतार ले भाजपा का साधारण सा कार्यकर्ता जीतकर आएगा।

कांग्रेस के कर्ज वाले बयान पर राजेश मूणत ने कहा कि राज्य चलाने की चिंता भाजपा पर है। हमने छत्तीसगढ़ बनाया, हम ही संवारेंगे। कांग्रेस ने कितना कर्जा लिया सबके सामने है? डबल इंजन की सरकार है, अभी-अभी सरकार बनी है। सरकार को सात महीने हुए हैं। कांग्रेस तड़पने लगी है, चिंता न करें।

भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार के गौ नीति पर उठाए गए सवाल पर राजेश मूणत ने कहा कि भूपेश बघेल अपने कार्यकाल का पन्ना पलट लें। गौठान की क्या हालत थी? प्रदेश के पंचायत को पार्टी के लिए चारागाह बना दिया था। आज भी सरपंच दुखी हैं कि पैसा कहां गया। करोड़ों-अरबों रुपये राजीव मितान क्लब के नाम पर खर्च करके चले गये। खेल का बढ़ावा तो नहीं हुआ लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जेब जरूर भर ली। इसका जीता जागता उदाहरण मैंने विधानसभा में दिया है।

पीडीएस मामले में ईडी का सुको में बड़ा खुलासा

■ हाईकोर्ट जज के संपर्क में थे घोटाले के दो आरोपी अफसर

रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक हजार करोड़ रुपये के कथित नागरिक आपूर्ति निगम घोटाला (पीडीएस) मामले में बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। इस मामले में शामिल दो अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज से संपर्क किया था। ईडी ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है। ईडी ने एससी को दिये अपने हलफनामे में दावा करते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की तत्कालीन भूपेश सरकार के दो नौकरशाह अपने खिलाफ चल रहे मामले को कमजोर करने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश किये थे। हालांकि, एक अगस्त के हलफनामे में ईडी के संबंधित जज का नाम नहीं बताया गया है, लेकिन व्हाट्सएप चैट डिटेल्स से मालूम चला है कि वह जस्टिस अरविंद कुमार चंदेल ही थे। ईडी ने दावा करते हुए कहा कि उनसे उनके भाई और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव अजय सिंह के जरिए संपर्क किया गया था।

ईडी ने इस संबंध में दावा करते हुए कहा कि इस मुकदमे को की जांच को प्रभावित करने के लिए हमारे पास पर्याप्त सबूत हैं। टुटेजा तत्कालीन एडवोकेट जनरल सतीश चंद्र वर्मा के माध्यम से न्यायाधीश के संपर्क में थे। यह 31 जुलाई और 11 अगस्त 2019 के व्हाट्सएप से मिले संदेशों से क्लीयर है। व्हाट्सएप संदेशों से पता चला है कि न्यायाधीश की बेटी और दामाद का बायोडाटा तत्कालीन एजी की ओर से अनुकूल कार्रवाई के लिए टुटेजा को भेजा गया था, जो न्यायाधीश और दोनों मुख्य आरोपी टुटेजा और शुक्ला के बीच कोर्डिनेट का काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को ईडी ने दावा करते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ के नागरिक जन आपूर्ति निगम घोटाले में आरोपी दो वरिष्ठ नौकरशाह अनिल कुमार टुटेजा और आलोक शुक्ला अक्टूबर 2019 में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज के संपर्क में थे। उसी जज की अदालत से 16 अक्तूबर 2019 को आलोक शुक्ला को जमानत पर रिहाई का आदेश जारी हुआ था। इतना ही नहीं ईडी का दावा है कि तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा दोनों दागियों और न्यायाधीश के बीच संपर्क बनाए हुए थे।

सावन सोमवार को महादेवघाट में उमड़े श्रद्धालु

■ बजरंग बली ने यहां रखा था शिवलिंग

रायपुर। सावन महीने के तीसरे सोमवार को रायपुर के शिव मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। सुबह 5 बजे से ही लोगों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। राजधानी के पूरे शिवालय हर-हर महादेव की जयघोष से गूंज रहे हैं। रायपुर के महादेवघाट स्थित हटकेश्वरनाथ मंदिर में सावन के पहले दिन भारी संख्या में शिवभक्तों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान भगवान हटकेश्वरनाथ महादेव की मंत्रोच्चारण के बीच विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई।

हरिद्वार के लक्ष्मण झूला की तर्ज पर यहां बने लक्ष्मण झूला और खारून नदी में नाव की सवारी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। पास में बने गॉर्डन यहां की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। रायपुर सहित अन्य जिलों के सैलानी यहां बड़ी संख्या पहुंचकर इसका आनंद लेते हैं। शहर की जीवनदायिनी नदी खारुन तट पर स्थित ऐतिहासिक हटकेश्वरनाथ मंदिर का विशेष महत्व है।

1402 ई में कल्चुरी वंश के राजा रामचंद्र के पुत्र ब्रह्मदेव राय के शासन काल में हाजीराज नाइक ने मंदिर का निर्माण करवाया था। ऐसी मान्यता है कि यहां नंदी महाराज के कानों में जो भक्त फरियाद या मन्नत मांगते हैं, उसकी भगवान शिव मुरादें जरूर पूरी करते हैं। सावन के महीने में यहां रायपुर और प्रदेश के कोने-कोने

से लोग पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ के कई जिलों से श्रद्धालु कांवर लेकर पहुंचते हैं। हर साल कांवर पदयात्रा भी निकाली जाती है।

धार्मिक मान्यताओं और पुराणों के अनुसार, जहां भगवान श्रीराम लंका पर चढ़ाई के लिए रामेश्वरम में समुंद्र पर पुल बनाने की योजना बनाई तो उस समय बजरंग बली को शिवलिंग लाने के लिए कहा गया था। इस पर बजरंग बली शिवलिंग लाने गए। इस दौरान शिवलिंग लाने में काफी देर हुई, तो भगवान राम ने रामेश्वरम में रेत से ही विधि-विधान से पूजा अर्चना कर शिवलिंग की स्थापना कर दी थी। बजरंग बली को किसी नदी के किनारे उस शिवलिंग को रखने के लिए कहा गया। कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने रायपुर में खारून नदी के तट पर शिवलिंग रखकर चले गए, जो कालांतर में हटकेश्वर नाथ, महादेव घाट के नाम से विख्यात हुआ।

2 तालाबों के बीच विराजित है पंचमुखी शिवलिंग

रायपुर के सरोना गांव में प्राचीन शिव मंदिर में दर्शन करने सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। 250 साल पुराने इस पंचमुखी शिव मंदिर में सावन के तीसरे सोमवार को दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। भक्त लाइन में लगकर अपनी-अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। मंत्रोच्चारण के बीच पंचमुखी भगवान शिव का मनमोहक श्रृंगार किया गया। इस दौरान मंदिर परिसर में बम-बम भोले के जयकारे लगते रहे। पूरा मंदिर परिसर जयकारों से गूंजता रहा। यह मंदिर दो तालाबों के बीच में बना हुआ है। दोनों तालाब इस मंदिर की खूबसूरती बढ़ाते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर के नीचे से तालाब का पानी बहता है। लोग इसे कछुआ वाले शिव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। दोनों तालाब में 100 साल से अधिक उम्र के दो कछुओं समेत कई कछुए रहते हैं, जिसे देखने के लिए श्रद्धालु घंटों तालाब के किनारे खड़े रहते हैं। मंदिर के पुजारी शंकर गोस्वामी ने बताया कि इस मंदिर को राजपूतों ने बनवाया था।

कार्यालय उमनि/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जिला गरियाबंद (छ.ग.) निविदा आमंत्रण हेतु कार्य की सूची

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. पुअ/गरि/ 123 /AC-1/2024 गरियाबंद, दिनांक 23/07/2024

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से लोक निर्माण विभाग/R.E.S में पंजीकृत ई पंजीयन के तहत् डी वर्ग या ऊपर श्रेणी के ठेकेदार प्रपत्र अ में प्रतिशत दर पर, छत्तीसगढ़ शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी भवन कार्य के एस.ओ.आर. 01.01.2015 के आधार पर निम्नलिखित तिथि को अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में मुहरबंद दो लिफाफा पद्धति के तहत् रजिस्टर डाक स्पीड पोस्ट/By hand निविदाएं आमंत्रित की जायेगी। निविदा से संबंधित तिथियां निम्नानुसार है:- 1. निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि:-20/08/2024 अपरान्ह 05.00 बजे तक 2. निविदा प्रपत्र कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि : 21/08/2024 अपरान्ह 03:00 बजे तक 3. निविदा खुलने की तिथि:- 21/08/2024 सायं 04:00 बजे से। (उपरोक्त में से किसी तिथि को शासकीय अवकाश घोषित होने की स्थिति में आगामी कार्य दिवस में पूर्व निर्धारित समय तक मान्य किया जावेगा।)

टीप:- नक्सल प्रभावित पुलिस विभाग जिला गरियाबंद में कार्य किये हुए अनुभव प्राप्त एजेंसी से निर्माण कार्य कराया जायेगा।

स.क्र.	कार्य का विवरण	कार्य की लागत	अमानत राशि टी.डी.आर. के रूप में
1	2	3	4
1	पुलिस थाना राजिम में 02 नग बैरक निर्माण कार्य	10.00 लाख (प्रति नग)	7500

नोट:- निविदा प्रपत्र का मूल्य 750/- एवं कार्यपूर्ण करने का समय 02 माह वर्षा काल सहित होगी। निविदा की अन्य नियम व शर्तें एवं जानकारी पुलिस अधीक्षक कार्यालय, गरियाबंद से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

वरि. पुलिस अधीक्षक
जिला-गरियाबंद (छ.ग.)

जी-242501599/3

आरक्षण के स्वरूप में बदलाव जरूरी

प्रभु चावला

सहस्राब्दियों से जाति भारतीय मानस में पत्थर की तरह ठोस पैठ बना चुकी है। विडंबना ही है कि लोकतंत्र बनने के बाद भी भारत में भेदभाव की विरासत जारी रही। सामाजिक ढांचे को सिर के बल खड़ा कर दिया गया, पर जाति आधारित परिवारवाद भी बिना चुनौती के फलता-फूलता रहा। राजनीति एवं नौकरशाही में धनी एवं ताकतवर वंशगत विरासत इस व्यवस्था को पोषित करती रही है। पर बीते सप्ताह आया सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय इस व्यवस्था को पटरी से उतार सकता है। संसद, चुनाव एवं संस्थानों में जाति पर चल रहे वर्तमान शोर ने शीर्षस्थ न्यायालय के सात न्यायाधीशों की एक संवैधानिक पीठ ने उद्वेलित कर दिया। न्यायाधीश बीआर गवई के नेतृत्व में चार न्यायाधीशों ने रेखांकित किया कि जातिगत आरक्षण मेधा से संबंधित है, न कि नौकरशाही या धन तंत्र से। न्यायाधीश गवई ने लिखा है कि सरकार को अनुसूचित जाति एवं जनजाति में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए नीति बनानी चाहिए, जिससे उन्हें आरक्षण के दायरे से हटाया जा सके। इसी उपाय से संविधान में निहित समानता को सही अर्थों में साकार किया जा सकता है। उन्होंने पूछा है कि क्या एक बड़े अधिकारी की संतान को पंचायत या जिला परिषद के विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे के समकक्ष रखा जा सकता है। यदि गीता भारत की आत्मा है, तो जाति इसका अभिशाप है। जो व्यवस्था सहस्राब्दियों पहले पेशेवर पहचान के रूप से प्रारंभ हुई, वह कालांतर में भ्रष्ट होकर चुनाव जीतने का एक पैंतरा बन गयी। जातिगत आरक्षण की शुरुआत लगभग 125 साल पहले हुई। अनुसूचित जातियों और जनजातियों की दुर्दशा को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका एवं विधायिका में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की, जो एक अस्थायी प्रावधान था और उसकी अवधि दस वर्ष थी। भारतीय राजनीति को यथास्थिति पसंद है और इसे बदलाव से परहेज है। किसी दल ने उस प्रावधान में फेर-बदल नहीं किया है। उन्होंने जाति प्रथा को अपने चुनावी घोषणापत्र के लिए आरक्षित रखा है। आरक्षण का उद्देश्य स्वतंत्रता के बाद की पहली वंचित पीढ़ी के सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को बेहतर करना था। लेकिन वह अब तीसरी पीढ़ी का एक विशेषाधिकार बन गया है। आरक्षण का आशय समानता लाने का एक माध्यम बनना था। अब यह सामाजिक अभिजन के अल्पाधिकार और एकाधिकार का युग्म बन गया है। सत्ता पर अपने हिस्से के नियंत्रण से दलित एवं पिछड़े शाहों ने एक विशिष्ट सुरक्षा घेरा बना लिया है, जिसमें निचले पायदान पर खड़े लोगों का प्रवेश वर्जित है। जब सत्ता ने अपने लाभ को सर्वोच्च बना लिया है, तो नियंत्रण एवं संतुलन के संवैधानिक सिद्धांत का हस्तक्षेप हुआ है। न्यायाधीश गवई ने रेखांकित किया है कि विषमता और सामाजिक भेदभाव, जो ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक व्याप्त हैं, शहरी क्षेत्रों की ओर आते-आते कम होने लगते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अच्छे संस्थानों के छात्र तथा पिछड़े और दूर-दराज के क्षेत्रों में पढ़ रहे छात्र को एक ही श्रेणी में रखना संविधान के समता के सिद्धांत को भुला देना है। न्यायाधीश पंकज मित्तल ने कहा है कि आरक्षण को पहली पीढ़ी या एक पीढ़ी तक सीमित रखा जाना चाहिए तथा अगर एक पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ उठाकर उच्च हैसियत पा ली है, तो तार्किक रूप से अगली पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। यदि इस न्यायिक रुख को केंद्र और राज्य स्वीकार कर लेते हैं, तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ऐसे परिवार को आरक्षण नहीं मिलेगा, जिसने इस व्यवस्था का लाभ पहले उठा लिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने चुनिंदा जातियों के आरक्षण के लाभ में बदलाव कर इसे समावेशी बना दिया है तथा अब आरक्षण के दायरे में ऐसी उप-जातियां आ सकेंगी, जो पीछे रह गयी हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए वे लोग योग्य नहीं हैं, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपये से अधिक है। इसमें विसंगति यह है कि कृषि आय को कुल आय में नहीं जोड़ा जाता है। ऐसे में जमीन वाले पिछड़े वर्ग के परिवार आरक्षण का लाभ उठाते हैं। राजनेता न्यायिक सलाह को नहीं सुनेंगे। चूंकि आरक्षण का श्रेणीकरण विधायिका के तहत है, इसलिए ऐसी संभावना बहुत ही कम है कि नेताओं और अफसरों का गठजोड़ न्यायपूर्ण स्थिति के लिए प्रयासरत होगा।

नकारात्मक राजनीति की पीठ पर सवार है विपक्ष

डॉ. आशीष वशिष्ठ

एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जितनी जरूरत एक सशक्त सरकार की होती है, उतना ही सशक्त विपक्ष भी जरूरी होता है। विपक्ष लोकतंत्र के वास्तविक सार के संरक्षण और लोगों की आकांक्षाओं व अपेक्षाओं के प्रकटीकरण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किंतु, वर्तमान में भारत का विपक्ष झूठ और दुष्प्रचार की राजनीति में गले तक डूबा दिखाई देता है।

एक जीवंत लोकतंत्र में विपक्ष एक निगरानीकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण और संतुलन सुनिश्चित करता है। यह विभिन्न विचारों को व्यक्त करने, समाज के विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने और सरकार को उसके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने में सहायक होता है। एक दशक तक लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद रिक्त रहा, क्योंकि सदन में किसी भी पार्टी के पास सदन की कुल सदस्य संख्या के दसवें हिस्से के बराबर सदस्य नहीं थे, जो अब रायबरेली के सांसद राहुल गांधी द्वारा भरा गया है। लेकिन राहुल गांधी विपक्ष के नेता संसदीय सीमाओं, अनुशासन, परंपराओं और कर्तव्यों की लक्ष्मण रेखा प्रतिदिन लांघ रहे हैं। राहुल गांधी संसद में खड़े होकर जो मन में आता है, बोलते हैं। उनके भाषण का कोई सिरा आपस में जुड़ता नहीं है। असल में वो रटी रटाई स्क्रिप्ट को सदन में दोहराते हैं। वो सरकार पर निशाना साधने और उसकी साख को गिराने के एजेंडे को हर दिन आगे बढ़ाते हैं। चुनाव नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी के संसद में दिये गये भाषणों और मीडिया के सामने की गयी बयानबाजी का विश्लेषण करें तो वो सीधे तौर पर देश के हर तबके और वर्ग में असंतोष पैदा करने में जुटे हैं। वो मोदी सरकार की साख पर बट्टा लगाने के मिशन में जुटे हैं। विपक्ष के नेता और विपक्ष की भूमिका के इतर वो हर वो काम कर रहे हैं, जो विशुद्ध तौर पर राजनीति का हिस्सा है।

संसदीय व्यवस्था में विपक्ष की भूमिका की बात करें तो विपक्ष सरकार की नीतियों और कार्यों की जांच करता है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए, भारत में 2जी स्पेक्ट्रम

मामले में विपक्ष द्वारा निभाई गई भूमिका ने भ्रष्टाचार और शासन के मुद्दों को उजागर किया। विपक्ष नीतिगत मामलों पर वैकल्पिक दृष्टिकोण भी प्रदान करता है। 2013 में विपक्ष के रूप में भाजपा ने तत्कालीन यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियों की प्रभावी ढंग से आलोचना की, जिससे उसे महत्वपूर्ण चुनावी लाभ हुआ।

वहीं विपक्ष विविध और अल्पसंख्यक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे बहुलवादी समाज सुनिश्चित होता है। डीएमके और एआईटीसी जैसी क्षेत्रीय पार्टियां राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इन सबके अलावा विपक्ष विधायी प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे अक्सर कानूनों में सुधार होता है। मौजूदा सरकार के तहत जीएसटी विधेयक में विपक्ष द्वारा सुझाए गए संशोधन इसका एक उदाहरण हैं।

1960 के दशक के आरंभ से भूमि सुधार, औद्योगिक मज़दूर वर्ग के अधिकार, बेरोज़गारी, खाद्यान्न एवं उनका वितरण, जातीय मांगों और भाषाई अधिकारों जैसे विभिन्न मुद्दों पर पूरे भारत में शक्तिशाली आंदोलनों की शुरुआत हुई। तत्कालीन विपक्ष ने स्वयं को इन सामाजिक आंदोलनों से उल्लेखनीय रूप से संलग्न किया था। इतिहास में संसदीय विपक्ष ने भारत के संसदीय लोकतंत्र को रचनात्मकता और सकारात्मकता प्रदान की थी।

वहीं इस बात में दो राय नहीं है कि कमज़ोर विपक्ष एक कमज़ोर या गैर-उत्तरदायी सरकार से कहीं अधिक खतरनाक होता है। और एक गैर-उत्तरदायी, अनुशासहीन और संसदीय परंपराओं को न मानने वाला विपक्ष देश को तबाही की रास्ते पर ले जाता है।

4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही विपक्ष ने इंडी गठबंधन के बैनर तले मोदी सरकार को हर छोटे—बड़े मुद्दे पर घेर रहा है। खासकर देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस संसदीय नियमों, लोकतंत्र की मर्यादाओं और परंपराओं को भूलकर लगातार तीन लोकसभा चुनाव में मिली हार की खीझ उतारती दिख रही है।

पिछले तीन आम चुनाव में ये तो साबित हो चुका है कि सीधी लड़ाई में विपक्ष मोदी को शिकस्त देने में सक्षम नहीं है। विपक्ष के झूठ, दुष्प्रचार और गलत बयानबाजी के बावजूद देश के हर वर्ग का विश्वास मोदी के प्रति कायम है। ऐसे में इंडी गठबंधन ने झूठ, दुष्प्रचार और विवादित मुद्दे उछालने की रणनीति पर काम करना शुरू कर रखा है।

2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने दुष्प्रचार और झूठ का सहारा लिया है। मोदी तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो संविधान बदल देंगे। भोली भाली जनता विपक्ष के दुष्प्रचार के दुष्चक्र में फंसी भी। इस चुनाव में विपक्ष की सीटें 2014 और 2019 के चुनाव की तुलना में बढ़ोत्तरी हुई। विपक्ष के झूठ और दुष्प्रचार के बावजूद मोदी के नेतृत्व में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की झोली में सबसे ज्यादा 240 सीटें डाली। जमीनी सच्चाई यह है कि तीसरी बार कांग्रेस विपक्ष में बैठने को मजबूर है। देश की जनता ने उसे सत्ता के लायक नहीं समझा। इस चुनाव में झूठ, षडयंत्र, दुष्प्रचार और पूरी ताकत लगाने के बावजूद विपक्ष सत्ता के करीब नहीं पहुंच पाया। लगातार तीन चुनाव में हार की खीझ, झुंझलाहट, हताशा और निराशा विपक्ष के नेताओं की बयानबाजी में साफ तौर पर झलकती है।

विशेषकर गांधी की गतिविधियां, भाषण और बयानबाजी से ऐसा प्रतीत होता है कि वो देश में अराजकता पैदा करना चाहते हैं। राहुल गांधी कभी अग्निवीर और नीट परीक्षा की आड़ में युवाओं को, कभी किसानों को, कभी अल्पसंख्यक समुदायों को, कभी सरकारी कर्मचारियों को, कभी दलित और आदिवासियों के मन में सरकार, संवैधानिक संस्थाओं और व्यवस्था के प्रति रोष, असंतोष और घृणा भरने का काम कर रहे हैं। वो तो देश की जनता इतनी परिपक्व और समझदार है कि वो इनके कुत्सित इरादों ओर नीयत को समझती है। अगर जनता की समझदारी में थोड़ी भी कमी या अपरिपक्वता होती तो चार जून के बाद से अब तक देश में हिंसा और सांप्रदायिक तनाव की कई घटनाएं घट गयी होती। देश में अशांति, असुरक्षा और भय का वातावरण बन गया होता। देश की समझदार और परिपक्व जनता इस समझदारी, धैर्य और अनुशासन के लिये बधाई की पात्र है।

राजनीतिक दल अपनी राजनीति चमकाने और आगे बढ़ाने के लिये विरोधी दल की आलोचना करते हैं। ये आम बात है। लेकिन विरोध नीतियों, नीयत और निर्णयों पर होना चाहिए। वहीं विरोध और आलोचना में सत्य, प्रामाणिकता और सकारात्मकता होनी चाहिए। आधे अधूरे तथ्यों, जानकारी और आंकड़ों के आधार पर एक दूसरे की आलोचना करना एक स्वस्थ लोकतंत्र में उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पिछले एक दशक से विपक्ष झूठ, दुष्प्रचार, फेक न्यूज फैलाने और झूठे नैरेटिव गढ़ने में व्यस्त है। उसके पास देश की समस्याओं के समाधान की कोई कार्ययोजना और नीति नहीं है। देश के विकास और जनकल्याण का कोई मॉडल और विजन उसके पास नहीं है। विपक्ष झूठ के सहारे सत्ता हासिल करना चाहता है। और देशवासियों की समस्याओं के समाधान के तौर पर रेवड़ी कल्चर का पिटारा उसके पास है। लोकतंत्र का स्वास्थ्य प्रायः उसके विपक्ष की ताकत और जीवंतता में झलकता है। भारत में विपक्ष को मजबूत करना सिर्फ़ राजनीतिक दलों को सशक्त बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने के बारे में भी है। राज्य द्वारा वित्त पोषण, मीडिया तक समान पहुंच और पार्टियों के भीतर आंतरिक लोकतंत्र को बढ़ावा देने जैसे उपाय महत्वपूर्ण हैं। एक जीवंत, उत्तरदायी और जवाबदेह लोकतंत्र के लिए एक मजबूत और प्रभावी विपक्ष आवश्यक है। वर्तमान में विपक्ष अपनी भूमिका, कर्तव्यपालन और उत्तरदायित्व के पालने में असफल दिखाई देता है। विपक्ष को झूठ, दुष्प्रचार और नकारात्मक राजनीति छोड़कर देश और जनता के हित, कल्याण, समृद्धि और विकास की दिशा में कार्य करना चाहिए। इसी में लोकतंत्र, लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक दलों की भलाई और कल्याण निहित है।

पुराण दिग्दर्शन .... परिचयाध्याय

अविशिष्ट-क्रम (भाग-2)

गतांक से आगे...

अग्नि का भी उत्पादक सूर्य है इसलिए सूर्य या आदित्य मूल तत्त्व हैं यह तीसरी विप्रतिपत्ति है इसके निरूपणार्थ नवम भविष्यपुराण है। भविष्य में सूर्य को ही प्रधान परमतत्त्व कहा गया है। इस प्रकार मूल तत्त्व के सम्बन्ध में कई विप्रतिपत्तियाँ दिखा कर पुराण अपनी ओर से ब्रह्म को मूल तत्त्व बताता हुआ ब्रह्मवैवर्त दशम पुराण के द्वारा सिद्धान्त को स्पष्ट कर देता है। यों दश पुराण तक के क्रम से सृष्टि का पूर्ण विकाश और जगत् का मूल तत्त्व बता दिया गया है। अब वह मूल तत्त्व ब्रह्म किस प्रकार पहिचाना जाये? वह किन रूपों से किस प्रकार सृष्टि का निर्वाह करता है?

जीव अपने कल्याण के लिये कैसे उसकी उपासना करे- इत्यादि जिज्ञासाएँ उपस्थित होती हैं। उन्हें निवृत्त करने को आगे के छः पुराणों में उस परब्रह्म के अवतारों का निरूपण है। ग्यारहवां लिङ्गपुराण और तेरहवाँ स्कन्दपुराण भगवान् परम शिव के अवतारों का दिग्दर्शन कराते हैं। और 12वां वाराह, 13वां वामन, 15वाँ कूर्म्म, 16वां मत्स्य ये चारों भगवान् महाविष्णु के अवतारों का विवरण करते हैं।

यद्यपि भगवान् विष्णु के अनन्त अबतारों में 24 प्रधान आने गये हैं तथापि उनमें भी दश अवतारों की विशेष रूप से प्रधानता है यह सृष्टि विज्ञान का मनन करने पर समझ में आ सकता है: अस्तु, अब कर्भ उपासनादि के सम्बन्ध से जीव की विविध गति बताने को सत्रहवाँ गरुड़पुराण और उन सब गतियों का आयतन (आधार) बताने को अठारहवाँ ब्रह्माण्ड उपस्थित होता है। वों सपरिकर प्रधान विद्या का निरूपण अठारह पुराणों द्वारा हो जाता है, और आगे कोई ज्ञातव्य विषय शेष नहीं रहता । यही अविशिष्ट क्रम का रहस्य है।

क्रमशः ...

हिरोशिमा दिवस

अभिनय आकाश

ये 1945 की बात है 6 अगस्त की तारीख और जापान में सुबह आठ बज रहे थे। एक जोर का धमाका हुआ और कुछ ही मिनटों के अंदर एक हंसता-खेलता शहर एक राख के ढेर में तब्दील हो गया। हम दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान पर हुए परमाणु हमले की बात कर रहे हैं। इसके ठीक तीन दिन बाद यानी 9अगस्त को दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर गिरा और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। हिरोशिमा दिवस हर साल 6 अगस्त को शांति की राजनीति को बढ़ावा देने और हिरोशिमा पर बम हमले के प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। हिरोशिमा शहर पर एक परमाणु हथियार से हमला किया गया था। जिसने 6 अगस्त, 1945 को पल भर में ही हजारों

लोगों की जान ले ली थी।

1945 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी की परमाणु बमबारी की वर्षगांठ को चिह्नित करते हुए आइर स्क्वायर में गॉलवे एलायंस वॉर में एक वार्षिक कार्यक्रम होता है। संगीत, नृत्य और गीतों के माध्यम से हर साल शांति राजनीति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध 1939- 1945 तक चला था, जब दुनिया का पहला परमाणु बम तैनात किया गया था। जिसमें 9000 पाउंड से अधिक यूरेनियम -235 लोड किया गया था और जिसे यूएस बी-29 बॉम्बर एयरक्राफ्ट, एनोला गे द्वारा 6 अगस्त 1945 को जापानी शहर हिरोशिमा पर गिराया गया था।हिरोशिमा पर गिराए गए बम का नाम लिटिल ब्वॉय था। ये करीब चार हजार किलो वजन का था। नागासाकी शहर पर गिराए गए बम का नाम द फैट मैन था। इसका वजन 4500 किलो का था। इस विस्फोट में लगभग 80,000 लोग मारे गए थे और बड़े पैमाने पर ढांचागत क्षति हुई थी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 69 प्रतिशत इमारतें नष्ट हो गईं। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान अमेरिका और उसके सहयोगियों के खिलाफ था। जैसा कि सहयोगी युद्ध जीत रहे थे, चीन और जापान जैसे देशों को कई स्थानों से पीछे धकेल दिया गया था। जापानी सैनिकों ने ब्रिटिश और अमेरिकी सैनिकों के साथ क्रूर व्यवहार किया, जिसके परिणामस्वरूप परमाणु हमला हुआ। हिरोशिमा पर गिराए गए लिटिल ब्वॉय ने 2.5 किमी के दायरे में इमारतों को समतल कर दिया। बाद के समय में कई हजार लोग बीमार पड़ने वाले प्रभाव से मारे गए और घायल हो गए। यह दिन हमें परमाणु युद्ध की विनाशकारी स्थिति की याद दिलाता है। इस दिन, लोग हिरोशिमा शांति स्मारक संग्रहालय का दौरा करते हैं जो द्वितीय विश्व युद्ध में हिरोशिमा के परमाणु बमबारी को संग्रहीत करता है। आबे की सरकार ने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध को लेकर संयुक्त राष्ट्र के समझौते में हिस्सा नहीं लेने का फैसला लिया था। गौरतलब है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के अंत में अमेरिका ने जापान पर दो परमाणु हमले किए थे - पहला हिरोशिमा में और दूसरा नागासाकी में।

इजरायल का नया टारगेट अब कौन?

अभिनय आकाश

क्या खून के आंसू रोने वाला है इजरायल? ये सवाल इसलिए भी पूछा जाने लगा है कि हिजबुल्ला चीफ नसीरुल्ला ने धमकी दी है। लेकिन इजरायल तो जैसे इन सब से बेपरवाह कहता नजर आया आओ जरा तुम्हें भी देख लेते हैं। मीडिल ईस्ट में युद्ध की तपिश और तेज हो गई है। इजरायल ने हमास की कमर तोड़कर सभी को बेचैन करके रख दिया है। पहले हिजबुल्ला के मुख्य कमांडर फुआद शुक्र की हत्या हुई। फिर हमास चीफ इस्माइल हानिया का कत्ल हो गया। इन खबरों से अभी दुनिया हैरान ही थी कि इजरायल के प्रधानमंत्री का सार्वजनिक बयान सामने आया जिसमें वो कहते सुनाई पड़े कि जो कोई हमें नुकसान पहुंचाएगा हम उसका बदला चुकाएंगे। जो भी हमारे बच्चों की हत्या करेगा। हमारे नागरिकों की जान लेगा। उसका अंतिम समय नजदीक आ चुका है। 1 अगस्त को तेहरान में इस्माइल हानिया को दफन किया जा रहा था। जिस वक्त हानिया की अंतिम यात्रा चल रही थी उसी वक्त इजरायली डिफेंस फोर्स (आईडीएफ) ने एक्स पर लिखा कि अब हम दावे से कह सकते हैं कि मोहम्मद देऊफ मारा जा चुका है। देऊफ हमास के मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड का सरगना था। इस ब्रिगेड ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर आतंकी हमला किया था। तभी से वो इजरायल की हिट लिस्ट में था। इजरायल ने मानो पूरे मीडिल ईस्ट में बीते एक हफ्ते में खलबली सी मचा दी है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स और दुनिया की सबसे ताकतवर एजेंसी में

से एक मोसाद को लेकर भी कई सवाल उठाए जाने लगे थे। लेकिन इजरायल के ताबड़तोड़ एक्शन से हिजबुल्ला और हमास बुरी तरह से बौखला गए हैं। हिजबुल्ला ने इंतकाम तक लेने की कसम खा ली है।

हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह ने इजरायल को धमकी दी है। उसने कहा कि इजरायल ने सारी सीमा को पार कर दिया है और अब वो खून के आंसू रोने वाला है। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरल्लाह ने कहा कि हिजबुल्ला कमांडर फुआद शुक्र और इस्माइल हानिया की हत्या कर इजरायल ने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है। उसे प्रतिशोध का सामना करने के लिए अब तैयार रहना चाहिए। हिजबुल्ला चीफ ने कहा कि जंग अब नए चरण में प्रवेश कर गई है। आने वाले दिनों में इजरायल बहुत ज्यादा रोने वाला है। लोगों को खून के आंसू हम रूलाने वाले हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि इजरायल हर एक्शन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। चाहे ईरान की तरफ से पहले ऐलान किया गया कि हमला किया जाएगा। इन सबके लिए इजरायल तैयार दिखाई दे रहा है। इजरायल ने हमास और हिजबुल्ला दोनों को बड़ा दर्द दे दिया है। हालांकि हिजबुल्ला ने बदला लेना शुरू भी कर दिया है। फुआद शुक्र की हत्या के 48 घंटे के भीतर ही हिजबुल्ला ने लेबनान से इजरायल में रॉकेटों की बौछार कर दी और जबरदस्त तरीके से खलबली मचा दी। हिजबुल्ला ने इस बात का संकेत दे दिया है कि वो इजरायल पर हमला करके ही मानेगा। इजरायल ने हिजबुल्ला के कई रॉकेट को आयरन डोम की मदद से हवा में ही खत्म कर दिया। किसी रॉकेट को रिहाईशी इलाके में नहीं गिरने दिया गया। इसलिए इस रॉकेट हमले में किसी की जान के नुकसान की खबर नहीं आई है। इजरायल की तरफ से भी जवाबी कार्यवाही की गई है। लेबनान में हिजबुल्ला के ठिकानों पर इजरायल की तरफ से हवाई हमला किया गया है। इजरायल हमले के बचाव की तैयारी में जुटा है। आईडीएफ ने सभी रिजर्व और रेगुलर कॉमबैट डिविजन के साथ ड्रिल किया है। सभी की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई है। हिजबुल्ला के हमले के मद्देनजर उत्तरी इजरायल से आठ और समुदायों को शिफ्ट किया गया है। कुल 60 हजार से अधिक लोग सुरक्षित जगह पर भेजे जा चुके हैं। 40 किलोमीटर के दायरे से फैक्ट्री से खतरनाक सामग्री हटाने का आदेश दिया गया है।

लेबनान और इजरायल में जंग छिड़ी हुई है। इजरायल भी इस लड़ाई में इजरायल को जवाब देना चाहता है। इसलिए जल्द ही हमास का नया चीफ चुना जा सकता है। जिस रफ्तार से इजरायली खुफिया एजेंसी हमास को टारगेट कर रही है। उसके बाद गिनती के ही हमास विद्रोही बचे हैं। एक नया नाम सामने आया है जो हमास का नया चेहरा बन सकता है। इसका भारत के केरल से भी एक कनेक्शन है। इस्माइल हानिया की मौत के बाद उसकी गद्दी पर खालिद मसाल को जगह मिल सकती है। अभी तक संगठन की ओर से इसका ऐलान नहीं किया गया है। लेकिन जिस तरह से एक एक करके हमास के सभी नेता खत्म किए जा रहे हैं। हमास के पास कत्तान बनाने के लिए और कोई आतंकी नहीं बचा। हालांकि हमास चीफ की गद्दी पर बैठने के बाद खालिद कितने दिनों तक बचेगा इसकी गारंटी देना मुश्किल है। ऐसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद पहले एक बार खालिद को मारने की कोशिश कर चुकी है। 1997 में इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑर्डर पर खालिद को मारने की कोशिश हुई। इजरायली खुफिया एजेंट ने ओमान में खालिद को जहर का इंजेक्शन दिया था। खालिद मशाल को लेकर भारत में भी विवाद हो चुका है। उन्होंने पिछले साल 27 अक्तूबर को केरल के सॉलिडेरिटी यूथ मुवमेंट की तरफ से फिलिस्तीनियों के समर्थन में आयोजित ऑनलाइन रैली को संबोधित किया था। इस दौरान मशाल ने कहा था कि इजरायल से अल-अकसा मस्जिद को आजाद कराने और इजरायल के आतंक से फिलिस्तीनियों को बचाने में दुनिया को फिलिस्तीनियों का साथ देना चाहिए। ऑनलाइन रैली में हमास नेता के शामिल होने से केरल बीजेपी चीफ के सुरेंद्रन भड़क गए थे और उन्होंने मांग की थी कि आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की थी।

हमास के राजनीतिक चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद टेंशन बढ़ी हुई है। मीडिल ईस्ट में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी तनाव के बीच अमेरिका के भी इस जंग में कूदने की खबर आई है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये साफ कह दिया है कि अमेरिका हर हाल में इजरायल की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ है। वो ईरान और उसके प्रॉक्सी आतंकी संगठनों के खिलाफ इजरायल की सुरक्षा करने की बात भी अमेरिका की ओर से कही गई है। बाइडेन ने नेतन्याहू को फोन पर भरोसा दिलाया है। इसका ब्यौरा खुद व्हाइट हाउस ने जारी किया है। यानी अगर इजरायल पर कोई बड़ा हमला होता है तो अमेरिका उसमें खुद सीधे तौर पर शामिल हो जाएगा। इसके साथ ही इजरायल को भरोसा दिया गया है कि मिसाइल और ड्रोन के जरिए उसकी मदद की जाएगी। अमेरिका ने भरोसा दिलाया है कि इजरायल की हर तरफ से रक्षा की जाएगी।

आज का इतिहास

1825 बोलीविया ने पेरू से स्वतंत्रता हासिल की।
1890 ऑबर्न, न्यू यॉर्क, यूएस में ऑबर्न जेल में, विलियम केमलरलेबेक ने पहली व्यक्ति को एक इलेक्ट्रिक कुर्सी पर निष्पादित किया।
1930 ब्रिटेन के श्रम मंत्रालय ने 2 लाख बेरोजगार लोगो की लिस्ट बनायीं।
1930 न्यूयॉर्क सिटी के जज जोसेफ फोर्स क्रेटर रहस्यमय ढंग से गायब हो गए, अंततः उन्हें द मिसिंगेस्ट मैन इन द न्यू यॉर्क का खिताब मिला।
1935 हॉलीवुड में, कैलिफोर्निया . राल्फ विलार्ड, रूस में जॉर्जिया राज्य के एक डॉक्टर, ने प्रभावी रूप से जेकल नामक एक बंदर को जमे हुए और इसे वापस जीवन में लाया है।
1937 राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई।
1945 अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराए।
1945 परमाणु बम लिटिल बॉय हिरोशिमा पर संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गिराया गया है। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली बम है, जिसके कारण लगभग 140,000 लोग मारे गए थे।
1945 द्वितीय विश्व युद्ध-अमेरिकी सेना के वायु सेना के बमवर्षक एनोला गे ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एक परमाणु बम गिराया, जिसमें 140,000 से अधिक लोग मारे गए।
1951 कोरियाई सेना पश्चिमी कोरिया में चार दिनों तक सीधे अपने सहयोगियों के साथ लड़ी। अमेरिकी आठवीं सेना ने भोर में दुश्मन का सामना किया और कोरियाई बलों ने जवाबी हमले के साथ जवाब दिया।
1955 फ्रांस के दक्षिणी और अंटार्कटिक क्षेत्र को एक विदेशी क्षेत्र के रूप में बनाया गया।
1956 डुमोंट, दुनिया के पहले टेलीविज़न नेटवर्क में से एक है, जिसने इसके कार्यक्रम को प्रसारित किया।
1960 क्यूबा ने देश के सभी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण किया।
1962 जमैका में यूनाइटेड किंगडम का साम्राज्य समाप्त हुआ और उसे स्वतंत्रता मिली।
1962 जमैका ने यूनाइटेड किंगडम से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की, अंग्रेजी के 300 वर्षों के बाद मोरीथन ने स्पेनिश उपनिवेशवादियों से इसे1655 पर कब्जा कर लिया।
1964 अमेरिकी शोधकर्ता डोनाल्ड करी ने प्रोमेथियस को काटकर एक ब्रिसलकोन पाइन ट्राइकाउन किया था, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह सबसे पुराना ज्ञात क्लोनल जीव था, जिसकी खोज कम से कम 4,862 साल पुरानी थी।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नया अंतरजातीय संघर्ष शुरू होगा..!

अजय बोकिल

देश में एससी/ एसटी (अनुसूचित जाति/ जनजाति) वर्ग में भी उप श्रेणी यानी कोटे में कोटा को मंजूरी और इन दोनो आरक्षित श्रेणियों में भी ओबीसी की तर्ज पर क्रीमी लेयर तय करने के सुप्रीम को 6-1 के बहुमत से दिए फैसले के दूरगामी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिणाम होंगे। हालांकि कुछ लोगों ने इसे संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया है, लेकिन ज्यादातर हल्को में इस फैसले का स्वागत हुआ है, क्योंकि देश में आरक्षण की जो कहानी 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी, करीब डेढ़ सौ साल बाद इसमें एक नया और निर्णायक मोड़ आ गया है।

आजादी के बाद 70 सालों से सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की लाभार्थी जातियों के भीतर से आवाज उठने लगी थी कि आरक्षण का फायदा भी समान रूप से सभी जातियों को नहीं मिल रहा है। लिहाजा इस लाभ का वितरण नए और न्यायसंगत तरीके किया जाए।

दूसरे शब्दों में कहें तो आरक्षण का लाभ उठाकर आर्थिक व सामाजिक बेहतरी हासिल करने वाला एक नए किस्म का 'ब्राह्मणवाद' इन जाति वर्गों में भी आकार लेने लगा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सामाजिक न्याय के इसी आलोक में देखा जाना चाहिए, क्योंकि आरक्षित वर्ग के भीतर ही हितों के इस टकराव को लंबे समय तक अनदेखा नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राज्य अपने यहां आरक्षित श्रेणियों में अधिक लाभान्वित और कम लाभान्वित जातियों का वर्गीकरण कर सकेंगे। हालांकि यह काम बहुत सावधानी और पारदर्शिता से करना होगा। इसके लिए सही आंकड़े जुटाने होंगे। केवल वोटों की गोलबंदी के बजाए आरक्षण के समान वितरण की समुचित प्रक्रिया अपनानी होगी।

इस फैसले का विरोध जिन हल्कों से हो रहा है अथवा होगा, वे मुख्यत- वो जातियां हैं, जिन्हें आरक्षण का तुलनात्मक रूप से ज्यादा लाभ मिला है। कई जगह तो यह अब पीढ़ीगत रूप में भी बदल गया है।

दरअसल 'ब्राह्मणवाद' का सबसे बड़ा दोष भी उसका जन्मगत् होना ही है। पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण ने भी इसी प्रवृत्ति को आरक्षित वर्ग में पनपाया है। आरक्षण की सुविधा 'जन्मसिद्ध अधिकार' में बदलने लगी है। हालांकि, इस मान्यता के विरोधी यह कमजोर तर्क जरूर देते हैं कि पैसे और पद भर से वो सामाजिक प्रतिष्ठा और समानता नहीं मिलती, जिसकी कि दलित और आदिवासियों को पहली दरकार है।

मन से सामाजिक समता को स्वीकार करना और उसका आदर करना एक लंबी और दीर्घकालीन प्रक्रिया का हिस्सा है, जो जातिवाद की जो बुराई सैंकड़ों सालों में हिंदू समाज में गहरे तक घर कर गई है, उसका उच्चाटन होने में समय लगेगा। उसके लिए कानून के साथ-साथ मानसिकता बदलने की जरूरत है। धीरे- धीरे वह बदल भी रही है। लेकिन एक जातिविहीन अथवा समतामूलक समाज 'काल्पनिक आदर्श' स्थिति ज्यादा है।

इस बात का कोई ठोस पैमाना नहीं है कि वह कौन सी स्थिति होगी जिसे सौ फीसदी समता कहा जाएगा। क्योंकि सामाजिक समता के कई कारक है और समता अपने आप में परिस्थिति, अवसर और संसाधन सापेक्ष शब्द है। दूसरे, तथाकथित ऊंची और नीची जातियों

के बरक्स खुद आरक्षित जातियों के भीतर भी आंतरजातीय भेदभाव और छुआछूत कम नहीं है। इसे खत्म करना भी उतना ही जरूरी है।

आरक्षित जातियों में अवसरों का समान वितरण कैसे हो, इसके राजनीतिक रूप से प्रयास तो पहले से ही शुरू हो गए थे। मसलन दलितों में अति दलित अथवा महादलित, पिछड़ों में अति पिछड़ों को श्रेणियों में बांटकर उन्हें आरक्षण के लाभ देने की कोशिशें कुछ राज्यों ने पहले से शुरू कर दी थीं। लेकिन इसे सामाजिक न्याय के बजाए वोटों की गोलबंदी की पुनर्रचना के प्रयत्न के रूप में ज्यादा देखा गया। खासकर नीतीश कुमार ने बिहार में इसकी पहल तेजी की थी।

दुर्भाग्य से यह सच्चाई है कि आप किसी को कितना भी आरक्षण दें, लेकिन उसके वास्तविक लाभार्थी कुछ लोग अथवा जातियां ही होती हैं। अगर दलित या अनुसूचित जाति की ही बात करें तो देश में उनकी 16.6 फीसदी आबादी के आधार पर सरकारी नौकरियों में व शिक्षण संस्थानों में मोटे तौर पर 15 प्रतिशत और आदिवासियों को 8.6 प्रतिशत आबादी के हिसाब से 7.5 फीसदी आरक्षण दिया गया है।

अनुसूचित जाति वर्ग में यह आरक्षण कुल 1108 जातियों में बंटना होता है, लेकिन व्यवहार में वैसा होता नहीं है, क्योंकि सभी की सामाजिक आर्थिक परिस्थिति व चेतना अलग- अलग है। यही कारण है कि जिन आरक्षित जातियों में अपने हितों और स्वाभिमान को लेकर ज्यादा चेतना है, वो आरक्षण का लाभ उतना ही ज्यादा उठा पाते हैं। मोटे पर एससी श्रेणी में आरक्षण का फायदा करीब एक दर्जन जातियों ने ज्यादा उठाया है, जैसी कि जाटव, महार, मेहरा और अहिरवार आदि। लेकिन उन्हीं की एक हजार से आरक्षित बंधु जातियां इस मामले में बहुत पीछे छूट गई हैं।

अगर इस श्रेणी में सब कोटा होगा तो आरक्षण सुविधा का लाभ ज्यादा बेहतर और न्यायसंगत तरीके से वितरित हो सकता है। यही बात अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) वर्ग के लिए भी लागू होती है। वहां भी 744 जनजातियां हैं, लेकिन रिजर्वेशन का लाभ मुख्य रूप से गोंड, भील, संथाल आदि आदिवासियों ने ही उठाया है। इसका एक प्रमुख कारण शिक्षा और जागरूकता का अभाव भी है।

काफी कुछ यही स्थिति अति पिछड़ा वर्ग में भी हैं, जहां 5013 जातियां हैं, लेकिन लाभान्वित होने वाली प्रमुख जातियां यादव, कुणबी, कुर्मी, कलार, सोनी आदि ही हैं। हालांकि ओबीसी में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की शर्त लगा रखी है। जिसके मुताबिक वर्तमान में 8 लाख रू. वार्षिक आय से ज्यादा वाले परिवार ओबीसी आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते। जस्टिस रोहिणी आयोग ने भी अपनी रिपोर्ट में ओबीसी में सब कोटा बनाने की सिफारिश की है, जिस पर सरकार अभी खामोश है।

सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले में जिन चार जजो ने क्रीमी लेयर की शर्त को एससी/ एसटी में भी लागू करने का सुझाव दिया है, उनमें जस्टिस बी. आर. गवई भी शामिल हैं। इसके पीछे भाव यह है कि जिन लोगों को आरक्षण की वजह आर्थिक सामाजिक उत्थान हो जाए, वो आरक्षित सीट अपने दूसरे समाज व जाति बंधुओंके लिए खाली करें। खास बात यह है कि जस्टिस गवई स्वयं अनुसूचित जाति से हैं और योग्यता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में बाबा साहब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना के विपरीत है, क्योंकि आरक्षण जातीय समानता के मूल भाव से दिया गया था न कि आरक्षित जातीयों में भी वर्गीकरण करने के उद्देश्य से। प्रकाश अंबेडकर ने यह भी कहा कि अगर सब कोटा बनाना ही है तो अनारक्षित (अगड़ी) जातियों में भी इसे लागू किया जाना चाहिए। लेकिन वो यह भूल गए कि मोदी सरकार ने अनारक्षित जातियों के लिए आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर शेष बचे 50 फीसदी में से 10 प्रतिशत आरक्षण दे दिया है। यह भी सब कोटा ही है।

यहां अनारक्षित और आरक्षित जातियों में अवसरों और प्रगति का बड़ा अंतर इसलिए दिखता है, क्योंकि अनारक्षित श्रेणी में जातियों की संख्या न्यूनतम यानी 46 ही हैं, जिसमे अल्पसंख्यक आबादी (ओबीसी को छोड़कर) भी शामिल है।

अनारक्षित 50 फीसदी का लाभ इन्हीं में वितरित होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आरक्षित जातियो में से कोई भी अपना वर्ग छोड़कर इन अनारक्षित जातियों में शामिल नहीं होना चाहता। जबकि यहां अवसरों का वितरण बहुत कम जातियों में होता है। उल्टे जो जातियां अभी अनारक्षित हैं, वो भी आरक्षित में जाने के लिए लड़ रही है, जैसे कि महाराष्ट्र में मराठा जाति।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होने में वक्त लगेगा। क्योंकि इसके लिए जरूरी डाटा इकट्ठा करना होगा। हो सकता है कि सरकार अगले साल होने वाली जनगणना में इसे भी शामिल कर ले। लेकिन उसके भी पहले नई राजनीतिक गोलबंदियां तेज होंगीं। एससी/ एसटी में आरक्षण का ज्यादा लाभ उठाने वाली जातियां इस फैसले का विरोध करेंगी तो अल्प लाभ पाने वाली जातियां इसके समर्थन में जुटेंगी। यानी आरक्षित वर्गो में एक नया संघर्ष शुरू होने की संभावना है, जो सामाजिक न्याय और अवसरो की समानता की कोख से ही पैदा होगा।

जाहिर है कि राजनीतिक दल इसका अपने ढंग से लाभ उठाएंगे। इस साल के अंत में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनावों में यह बड़ा मुद्दा बन सकता है। हालांकि सरकार इस फैसले पर कैसे अमल करती है, करना चाहती भी है या नहीं, यह भी जल्द स्पष्ट होगा। बहरहाल देश सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई के एक नए दौर में प्रवेश करने वाला है, यह निर्विवाद है।

कोटे में कोटा का ये फैसला कैसे समीकरण बदल देगा

अभिनय आकाश

1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और गणतंत्र की नींव रखी गयी तो उसमें बराबरी नहीं थी। इसीलिए संविधान बनाते समय इसके निर्माताओं ने समानता का हक देते हुए भी कुछ अपवादों के लिए जगह छोड़ी। जिन वर्गों को ऐतिहासिक रूप से भेदभाव झेलना पड़ा है उन्हें आगे बढ़ने में राज्य मदद करे। इसी के नतीजे में आरक्षण की व्यवस्था अस्तित्व में आई। अनुसूचित जाति और जनजाति को कॉलेज और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। ताकि वो समाज में बाकी वर्गों के बराबर आ सकें। उनका प्रतिनिधित्व सरकार के समाज के हर स्तर पर हो सके। लेकिन आरक्षण के प्रावधान के साथ कुछ सवाल भी पूछे जाने लगे कि जो पिछड़ों में अगड़े हैं उनका क्या, आरक्षण का लाभ कितनी पीढियों तक या इसमें कोई इकोनॉमिक इनकम की कैप लगाई जाएगी? इसके साथ ही कानूनी आरक्षण के छत्र तले कब तक ये व्यवस्था रहेगी। देश की सबसे बड़ी अदालत की 7 जजों की बेंच ने एक फैसला दिया। 4 जजों ने कहा कि एससी-एसटी में भी क्रिमी लेयर होना चाहिए। इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और उसी के बारे में आज हम अपने लीगल बुलेटिन में विस्तार से बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुआई वाली बेंच इस बात का परीक्षण कर रही थी कि क्या पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति ऐक्ट- 2006 के तहत वाल्मीकि और मजहाबी सिख को रिजर्वेशन कोटे के तहत नौकरी में प्राथमिकता सकती है। साथ ही कोर्ट को यह देखना था कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भीतर राज्य सरकार सब-क्लास बनाकर रिजर्वेशन का लाभ दे सकती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में कुल 23 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। उनमें पंजाब सरकार की भी याचिका थी, जिसने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के 2010 के फैसले को चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने पंजाब लॉ की धारा 4(5) को खारिज कर दिया था जिसके तहत एससी कोटे में 50 फीसदी सीट वाल्मीकि और मजहाबी सिख को देने का प्रावधान था। हाई कोर्ट ने कहा था कि यह प्रावधान 2004 के सुप्रीम कोर्ट के चिन्नैया जजमेंट के खिलाफ है। 2004 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी के भीतर उप जाति को तरजीह देने को गलत बताया था। 2004 का फैसला पांच जजों की बेंच ने किया था। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 2004 के फैसले समय तहत राज्य सरकार के कानून को खारिज कर दिया था। राज्य सरकार ने किसी विशेष जाति को एससी-एसटी के सब क्लास में रखने के लिए कानून बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर उप-वर्गीकरण करना होगा, न कि मर्जी और राजनीतिक लाभ के आधार पर। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली सात-सदस्यीय संविधान पीठ ने 6:1 के बहुमत के निर्णय के जरिये ई वी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार मामले में शीर्ष अदालत की पांच-सदस्यीय पीठ के 2004 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों (एससी) के किसी उप-वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे अपने आप में स्वजातीय समूह हैं।

केंद्र और राज्यों के बीच सौहार्द बनाए रखना जरूरी

मनीषा प्रियम

संघवाद बनाम क्षेत्रवाद का संघर्ष भारतीय राजनीति में नया नहीं है। लेकिन अब यह ज्यादा उभर रहा है। हाल के दो मामलों में देखें, तो यह कुछ स्पष्ट होगा। 27 जुलाई को हुई नीति आयोग की बैठक में गैर- भाजपा शासित राज्यों के करीब दस मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा नहीं लिया। इंडिया गठबंधन से अलग होकर सं ममता बनर्जी जरूर इसमें शामिल हुईं, लेकिन वह भी यह आरोप लगाकर बाहर निकल गईं कि उन्हें अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उन्हें नियमानुसार बोलने का पर्याप्त समय दिया गया। साथ ही बारी से पहले बोलने के उनके आग्रह को भी स्वीकारा गया। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने माइक बंद करने के आरोप को भी गलत बताया। ममता के बीच में ही बैठक छोड़कर बाहर निकलने का राजनीतिक नतीजा यह हुआ कि नीति आयोग में प्रधानमंत्री ने जो एजेंडा सेट किया कि राज्यों के कल्याणकारी एवं विकासोन्मुख प्रशासन के वह कैसे वाहक बनेंगे, इस पर कोई विशेष चर्चा जनता के वीच नहीं हुई। सिर्फ पश्चिम बंगाल के क्षेत्रीय मामले बनाम केंद्र की राष्ट्रीय राजनीति ही सुर्खियां बनीं।

दूसरा मामला, झारखंड से भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने यह कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर नया केंद्रशासित प्रदेश बना देना चाहिए। इस बयान को भी ममता बनर्जी ने आड़े हाथों लिया और कहा कि वह बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगी। इससे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आग-बबूला हो सकते हैं। निशिकांत के बयान को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। वह एक संसदीय क्षेत्र के जनप्रतिनिधि यानी सांसद के अलावा अन्य किसी जिम्मेदार पद पर नहीं हैं। लेकिन राजनीति में तिल का ताड़ बनते देर नहीं लगती। विपक्ष पहले से ही इस

बात को लेकर हमलावर है कि भाजपा सरकार संविधान बदलना चाहती है। इस बयान को आधार बनाकर विपक्षी नेता आगामी कुछ महीनों में झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में प्रस्तावित विधानसभा चुनावों में भाजपा को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।

राज्य सरकारों और राज्यपालों के बीच टकराव की खबरें भी राष्ट्रीय समाचारों की सुर्खियां बनती रही हैं। इनमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और केरल की सरकारों के राज्यपालों से टकराव तो अदालतों तक पहुंच चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद संसद में विपक्ष के मजबूत होने से संघवाद बनाम क्षेत्रवाद की लड़ाई कम होने के बजाय बढ़ती दिख रही है।

लोकसभा चुनाव में एक तरफ सत्ताधारी दल भाजपा प्रभावशाली थी, तो दूसरी तरफ उसके विरोध में कई प्रांतों में क्षेत्रीय दल उठ खड़े हुए। यानी प्रतिस्पर्धा द्विदलीय न होकर भाजपा बनाम क्षेत्रवाद बन गई। दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में द्रमुक ने भाजपा को कड़ी टक्कर दी। चुनाव के पहले से ही मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और राज्यपाल आरएन रवि के बीच टकराव था। यहां तक कि राज्यपाल ने राज्य के संयुक्त विधानसभा सत्र की बैठक में अभिभाषण (जो राज्य सरकार द्वारा लिखित एवं अनुमोदित होता है) पढ़ने से इन्कार कर दिया था। ऐसा ही कुछ केरल में भी हुआ। यहां राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान एवं वामपंथी गठबंधन के मुख्यमंत्री पी विजयन के बीच सर्वाधिक मतभेद विश्वविद्यालयों में

कुलपति नियुक्ति को लेकर हुआ। कहने का मतलब कि हर मुद्दे पर जमकर राजनीतिक बहसबाजी हुई और राज्य सरकारों ने न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया। हालांकि कानूनी मसले थोड़े क्लिष्ट हैं, किंतु इससे स्पष्ट होता है कि वास्तव में यह लड़ाई राजनीतिक है। इस राजनीतिक दंगल का सबसे बड़ा प्रतिरूप पूर्वी राज्य पश्चिम बंगाल में भी देखा जा रहा है। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भाजपा से जमकर लोहा ले रही हैं। पिछले विधानसभा चुनाव (2021) में पश्चिम बंगाल में भाजपा ने बड़ी मुहिम चलाई थी। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव अभियान की बागडोर अपने हाथों में रखी। लेकिन ममता बनर्जी बांग्ला अस्मिता के नाम पर क्षेत्रवाद का झंडा बुलंद कर फिर से सत्ता में लौट आई।

अब तक माना जाता रहा है कि राज्यों के चुनाव में ही स्थानीय मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कुछ राज्यों में राष्ट्रीय मुद्दों के बजाय क्षेत्रीयता हावी रही। इस राजनीतिक लड़ाई के बीच जनता ने स्पष्ट किया कि भारत राज्यों की संघीय व्यवस्था है। पहली बार पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस न्यायालय के सहयोग से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा उनके ऊपर की जाने वाली टिप्पणियों पर प्रतिबंध लगा पाए हैं।

वहीं ममता बनर्जी ने भी सर्वोच्च न्यायालय के सामने यह गुहार लगाई है कि विधानसभा द्वारा पारित या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित आठ विधेयकों को राज्यपाल ने लंबे समय से लटकाए रखा है। राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति का मामला भी अधर में लटका हुआ है। न्यायालय ने राज्यपाल कार्यालय और केंद्र सरकार को इस मामले में नोटिस भी जारी कर दिया है। राज्यपाल इन आरोपों का खंडन करते हैं। कुल मिलाकर मामला भले ही न्यायालय में लड़ा जा रहा हो, पर यह वास्तव में केंद्र बनाम राज्य तथा संघवाद के ऊपर छिड़ी सघन राजनीतिक लड़ाई है।

अंतर्कलह से जूझती भाजपा की खराब होती दशा

कौशल किशोर

बीते लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल शुरू हुई। यह लगातार बढ़ रही है। आज उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव मोर्चे पर तलवार भांज रहे हैं। भाजपा के 100 विधायकों को तोड़ कर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने में मौर्य को मुख्यमंत्री का पद ऑफर किया गया था। सूबे में जारी इस घमासान का व्यापक असर देर-सवेर देश पर भी पड़ेगा। इसके कारण भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा की हालत ऐसी है कि देश का स्वास्थ्य मंत्रालय ही नेतृत्व विहीन प्रतीत होने लगा है।

उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुख्यमंत्री और उप-मुख्यमंत्री के बीच की तकरार सरहदें पार कर गई है। केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्य नाथ के नाम पर आज संगठन बनाम सरकार का समीकरण बन गया है। इसके बीच उत्तर प्रदेश की जनता की कौन सुनेगा? आज यक्ष प्रश्न यही है। लोकसभा चुनाव में भाजपा की ढलती स्थिति के लिए योगी को जिम्मेदार मान कर सत्ता से बेदखल करने का प्रयास अब तक सफल नहीं हो सका है। पार्टी नेतृत्व को याद होगा कि पूर्व में कल्याण सिंह की लोकप्रिय सरकार अंतर्कलह की भेंट चढ़ गई थी।

अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में हुई भूल के बाद भाजपा को सत्ता प्राप्त करने में 18 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। क्या मोदी के दौर में भाजपा फिर वही गलती दोहराएगी? इस सवाल के जवाब में तमाम तरह के दावे बाजार में मौजूद हैं। लोकसभा की 80 में से 75 सीटें जीतने का दावा करने वाले मात्र 33 पर सिमट गए। इसके कारण चुनाव में हार का ठीकरा फोडने की कवायद लगातार चलने लगी। लखनऊ में हुई समीक्षा में योगी आदित्य नाथ ने पार्टी की दुर्दशा के 3 कारण गिनाए।

पहला, उन्होंने भाजपा के 400 पार के नारे को अति आत्मविश्वास का प्रतीक करार दिया। दूसरा, संविधान बदलने की योजना को अनुकूल समझ कर इसे जनता ने

खारिज कर दिया। तीसरे कारण के रूप में डबल इंजन सरकार की सभी उपलब्धियों को जनता तक नहीं पहुंचा पाना माना। हालांकि पहले दोनों कारणों में उन्होंने दिल्ली की ओर उंगली घुमाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए शीर्ष नेतृत्व पर बराबर प्रहार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बायोलॉजिकल नहीं होने की बात पर भागवत भी राहुल गांधी की तरह चुटकी लेने से नहीं चूके थे।

सामाजिक समरसता के बदले हिन्दू मुस्लिम के नाम पर धुव्रीकरण के प्रयास पर उनकी प्रतिक्रिया चर्चाओं में है। भाजपा के करोड़ों कार्यकओं के सामने संघ के 50 लाख स्वयंसेवकों पर पार्टी अध्यक्ष नड्डा की बातों को उन्होंने अहंकार का प्रतीक माना है। इनका वास्तविक खमियाजा चुनाव में भुगतने के बाद संघ और भाजपा से जुड़ी हस्तियों की प्रतिक्रिया पर हार का टोटा हावी है। क्या विधानसभा उप चुनाव पर इस बात का असर नहीं होगा? उप-मुख्यमंत्री के रूप में 2 सहयोगी बैठाकर आलाकमान ने योगी जी पर अंकुश लगाने का काम किया।

विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए योगी की तैयारी चकित करती है। इसमें जीत दर्ज करने के लिए प्रदेश सरकार ने 30 मंत्रियों की टीम मैदान में उतारी है। दोनों उप मुख्यमंत्रियों को इससे बाहर रख कर उन्होंने आलाकमान को साफ संकेत दिया है। योगी की पसंद के 3 मंत्री प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को साधने का काम करेंगे। प्रतिपक्ष इस अंतर्कलह को भुनाने के प्रयास में लगा है। आलाकमान की शह पाकर ही केशव प्रसाद मौर्य बगावत को हवा दे रहे हैं। यह हिन्दू हृदय सम्राट और नेतृत्व शिखर पर बाबा के पहुंचने के मार्ग में बाधा खड़ी करने का काम है। इसके खिलाफ बुल्डोजर बाबा की रणनीति से चित्त और पट्ट का टॉस बाबा के पाले में है। त्याग पत्र की मांग करने वाले बैकफुट पर हैं।

मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया और छत्तीसगढ़ में डा. रमण सिंह की तरह उत्तर प्रदेश से योगीजी की विदाई आसान नहीं है। उनके राजनीतिक पैंतरे का असर भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री रहे इन सभी कद्दावर नेताओं पर पड़ेगा। अपनी हैसियत बनाए रखने के लिए मोदी, शाह व नड्डा कद्दावर नेताओं के पर कतरने से नहीं चूकते हैं। ऐसा पहली बार हुआ कि अनुशासित मानी जाने वाली पार्टी में बगावत इस कदर मुखर हो गई है। संघ और उत्तर प्रदेश की जनता का सहयोग, सहानुभूति व समर्थन योगी के साथ है। ऐसे में क्या भाजपा आलाकमान उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन कर सकेगी?

जातिवाद की इस राजनीति का गढ़ माने जाने वाले सूबे में ठाकुरवाद और वर्चस्व के समर्थन और विरोध में सक्रिय लोगों की कमी नहीं रही है। क्या आज पार्टी आलाकमान आसन्न संकट से अपना ही बचाव करती नहीं दिखती है? उत्तर प्रदेश विधानसभा उप-चुनाव के बाद इस पर फिर विचार करना होगा। देश के सबसे बड़े सूबे में सूबेदार बनने की होड़ में लगे नेता और अपनी कुर्सी बचाने में लगे शीर्ष पर बैठे नेता मिलकर एक दिन बाबा को शिखर पर पहुंचा कर ही दम लेंगे।

शब्द, सत्य और राजनीति के झमेले में जाति

गिरीश्वर मिश्र

यह सच है कि शब्द अपने प्रयोग से ही अर्थवान होते हैं पर यह भी सच है कि अर्थ शब्दों के प्रयोक्ता के मंतव्य के अधीन होते हैं इसलिए शब्द के अर्थ की स्थिरता निरपेक्ष नहीं होती। 'जाति' शब्द अर्थ की अस्थिरता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करता है। वैसे तो जाति शब्द किसी चीज की प्रकृति, समुदाय या श्रेणी के लिए प्रयुक्त होता है परंतु भारतीय समाज में यह शब्द समुदायों के नाम और पहचान का द्योतक बन चुका है। इसको लेकर समुदायों के बीच पारस्परिक सामाजिक संबंध बनते-बिगड़ते हैं। जातियों से अस्मिताओं का निर्माण किया जाता है और उनसे बनी पहचान भारतीय

सामाजिक जीवन का एक बड़ा सत्य है। जाति के साथ तादात्मीकरण व्यक्ति और समुदाय दोनों के लिए एक नियमबद्धता लाने वाला उपाय बन जाता है। एक जाति विशेष के लोग आपस में निकट आते हैं और दूसरी जाति से अपने को अलग करते हैं। सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी पर जातियां अलग-अलग पायदान पर स्थित होती हैं और सबका अपना-अपना दायरा होता है। आज जाति की शक्ति की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता, खास तौर पर राजनीति के क्षेत्र में तो ऐसा सोचना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हर कोई अपनी जाति से जुड़ कर या उसकी सदस्यता से अतिरिक्त ऊर्जा और बल का अनुभव करता है। जन्मसिद्ध होने के कारण जाति की सदस्यता व्यक्ति को स्वत: मिल जाती है और तब तक चलती रहती है जब तक उसे जाति से बहिष्कृत (कुजात!) नहीं कर दिया जाता। जन्मजात जाति व्यक्ति के साथ जीवनपर्यंत जुड़ी रहती है और अनेक औपचारिक तथा अनौपचारिक विषयों में हमारी गतिविधि को निर्धारित करती है। आज जाति व्यक्तिगत जीवन में एक संवेदनशील विषय बन चुका है। राजनीति के क्षेत्र में यह एक बेहद उपजाऊ सरोकार बन चुका है जिसे मुख्य आधार बना कर विभिन्न क्षेत्रों में चुनाव लड़े-लड़ाए जाते हैं और सरकारों का गठन और विघटन होता है। जाति को लेकर राजनीतिज्ञों की मुश्किल इसलिए बढ़ जाती है कि वे भेदभाव के अमानवीय आधार के रूप में इसके विरोध और खंडन में खड़े होते हैं जबकि खुद उनका राजनीतिक अस्तित्व जाति पर ही टिका होता है। उसी के समर्थन से वे चुने जाते हैं। वे बड़ी दुविधा में रहते हैं और कभी जाति का समर्थन तो कभी खंडन करते हैं। आज जाति और उपजाति सामाजिक स्तरीकरण और राजनैतिक दांव-पेंच का प्रबल आधार बन गई है। जाति की नई-नई श्रेणियां बनाई गईं और बनाई जा रही हैं। जातीयता और जातिवाद की भावना को जगा कर और एक-दूसरे को ऊंचा-नीचा दिखाकर सामूहिक जीवन पर अधिकार स्थापित करना राजनेताओं की नीति बनती गई है। आज की स्थिति में जाति का खंडन और मंडन दोनों साथ-साथ चल रहा है क्योंकि जातीयता की परिपुष्टि करना वोट बैंक का आधार है।

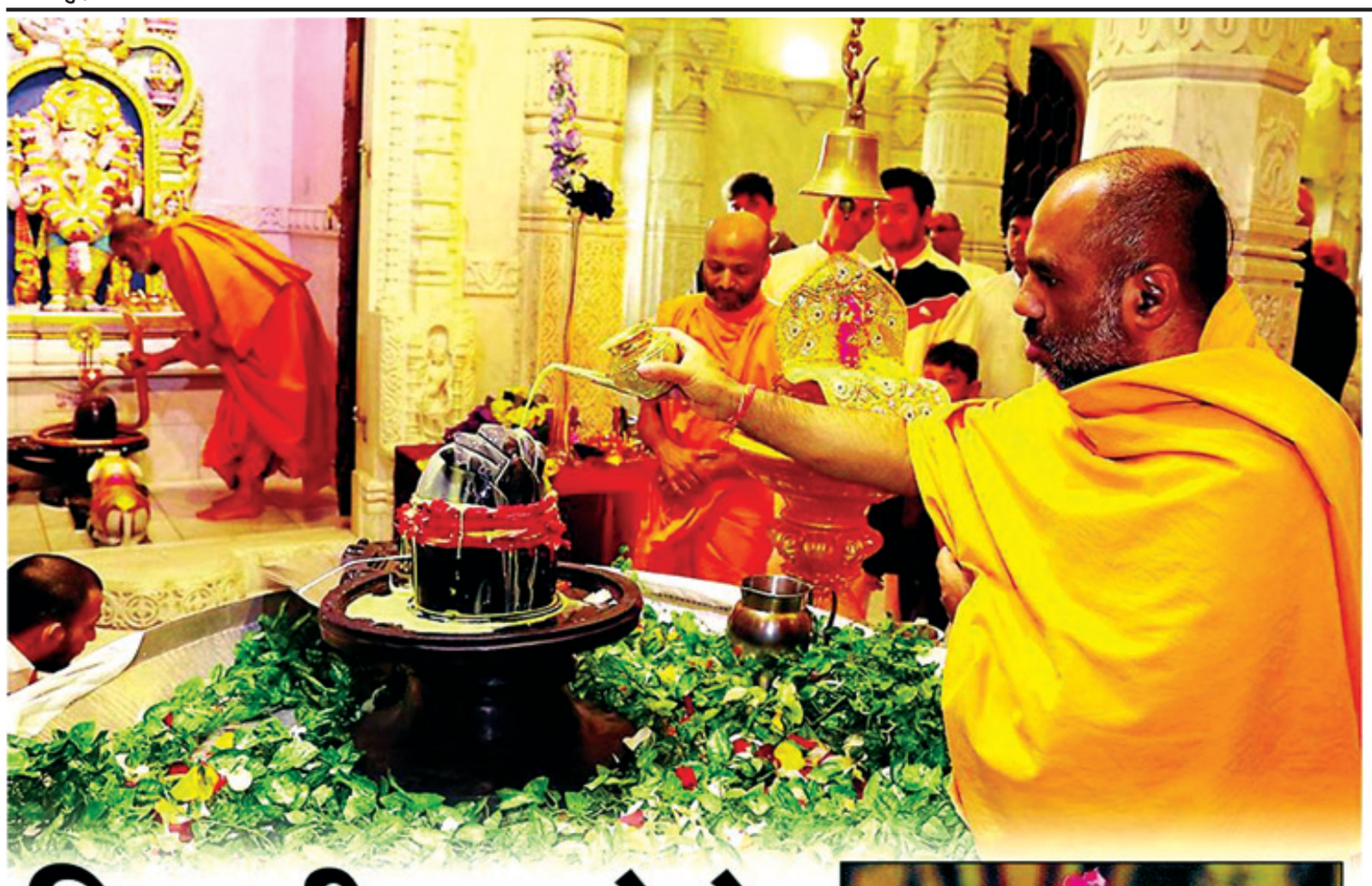

शिवजी का ऐसे करें अभिषेक सिद्ध होंगे सारे काम

सावन में महादेव की पूजा अभिषेक से की जाती है। शिवजी को जल, दूध दही, घी, शक्कर, गंगाजल, गन्ना रस से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद बेलपत्र, समीपत्र, दूब, कुशा, कमल, नीलकमल, ऑक मदार, जंवाफूल कनेर, राई फूल आदि चढ़ा कर प्रसन्न किया जाता है। इसके साथ ही भोग में धतूरा, भांग और श्रीफल महादेव को चढ़ाया जाता है।

शिव की इस दशा देख सभी देवता भयभीत

महादेव का अभिषेक करने के पीछे एक पौराणिक कथा का उल्लेख है कि समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकलने के बाद जब महादेव इस विष का पान करते हैं तो वह मूर्चिछत हो जाते हैं। उनकी दशा देखकर सभी देवी देवता भयभीत हो जाते हैं और उन्हें होश में लाने के लिए निकट में जो चीजें उपलब्ध होती हैं, उनसे महादेव को स्नान कराने लगते हैं। इसके बाद से ही जल से लेकर तमाम उन चीजों से महादेव का अभिषेक किया जाता है।

बेलपत्र और समीपत्र का महत्व

बेलपत्र और समीपत्र भगवान शिव को भक्त प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और समीपत्र चढ़ाते हैं। इस संबंध में एक पौराणिक कथा के अनुसार जब 89 हजार ऋषियों ने महादेव को प्रसन्न करने की विधि परम पिता ब्रह्मा से पूछी तो ब्रह्मदेव ने बताया कि महादेव सौ कमल चढ़ाने से जितने प्रसन्न होते हैं, उतना ही एक नीलकमल चढ़ाने पर होते हैं। ऐसे ही एक हजार नीलकमल के बराबर एक बेलपत्र और एक हजार बेलपत्र चढ़ाने के फल के बराबर एक समीपत्र का महत्व होता है।

पौराणिक कथा

बेलपत्र महादेव को प्रसन्न करने का सुलभ माध्यम है। बेलपत्र के महत्व में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक भील डाकू परिवार का पालन-पोषण करने के लिए लोगों को लूटा करता था। सावन महीने में एक दिन डाकू जंगल में राहगीरों को लूटने के इरादे से गया। एक पूरा दिन रात बीत जाने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिलने से डाकू परेशान हो गया। इस दौरान डाकू जिस पेड़ पर छुपकर बैठा था, वह बेल का पेड़ था और परेशान डाकू पेड़ से पत्तों को तोडकर नीचे फेंक रहा था। डाकू के सामने अचानक महादेव प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। अचानक हुई शिव कृपा जानने पर डाकू को पता चला कि जहां वो बेलपत्र फेंक रहा था उसके नीचे शिवलिंग स्थापित है। इसके बाद से बेलपत्र का महत्व और बढ़ गया।

भक्तगण अलग-अलग तरीकों से भगवान शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। हर कोई यह सोचता है कि किस तरह पूजा-पाठ करेंगे कि शिव की कृपा बनी रहे। वैसे तो शिव भगवान को भोले भंडारी कहते है जो सिर्फ भाव के भूखे है। वे श्रद्धा भाव से साधारण तरीके से की गई पूजा से भी खुश हो जाते है।

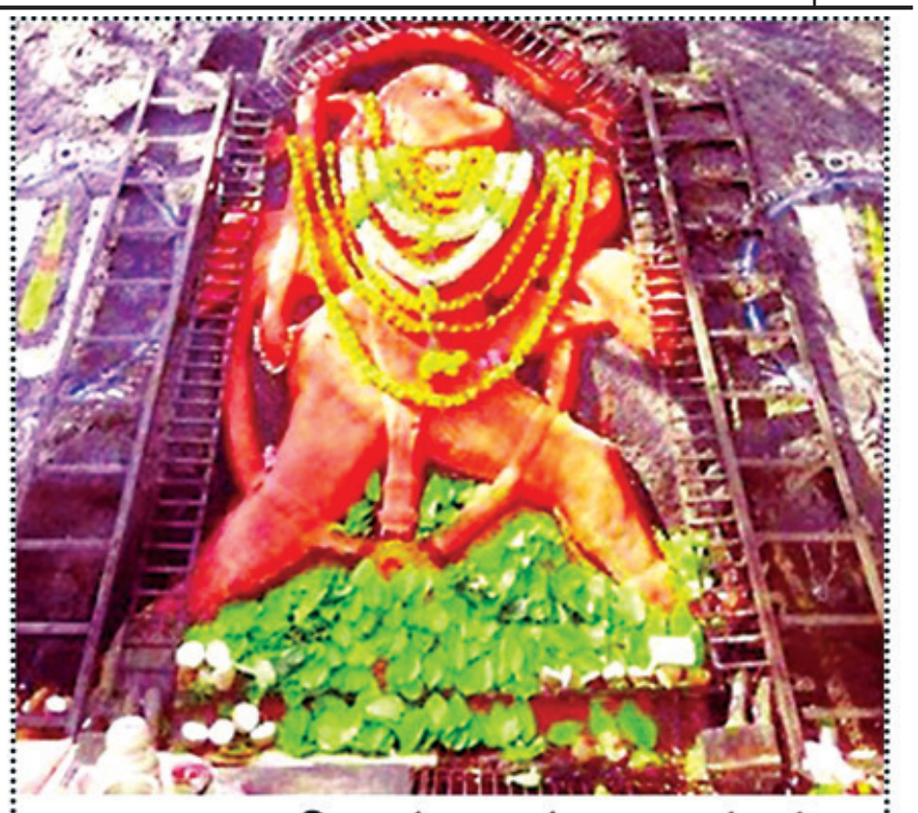

हनुमानजी को क्यों चढ़ाते हैं चमेली का तेल

चमेली का तेल हनुमानजी को चढ़ाने से वे जल्दी प्रसन्न होते हैं। लेकिन चमेली के तेल में ऐसा क्या है, जिसके कारण हनुमानजी प्रसन्न होते हैं। इसको जानने के लिए पहले चमेली के बारे में जानना होगा। दरअसल, चमेली का पारसी नाम यासमीन है। जिसका अर्थ होता है प्रभु की देन। जब यह फूल ही प्रभु की देन है तो फूल से बना हर पदार्थ भी प्रभु को प्रिय होगा। इस मान्यता के कारण बजरंगबली को चमेली का तेल सिंदूर के साथ लगाने से वह प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं।

- चमेली का फूल एक तरह की झाड़ी में लगता है, जिसकी लगभग 200 प्रजाति पाई जाती हैं।
- चमेली जैस्मिनम प्रजाति के ओलिएसिई कुल का फूल है।
- भारत से यह पौधा अरब के मूर लोगों द्वारा उत्तर अफ्रीका, स्पेन और फ्रांस पहुंचा था।
- इस प्रजाति की लगभग 40 जातियां और 100 किस्में भारत में अपने नैसर्गिक रूप में उपलब्ध हैं।
- चमेली सुगंधित फूल है, इसकी महक से लोग मोहित हो जाते हैं। चमेली के तेल से बहुत सारी दवाइयां बनायी जाती हैं, जो सिर दर्द, चक्कर, जुकाम आदि में काम आती हैं।

यह भी आजमाएं...

- हर मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंग बली को बना हुआ बनारसी पान चढ़ाना चाहिए।
- हनुमान मंदिर में भगवान के सामने हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार को करने से उनकी कृपा सदैव बनी रहती है।
- हनुमान मंदिर में जाकर रोज चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए।

इस तरह लगाएं भगवान को तिलक पूरी होंगी मनोकामना

शास्त्रों के अनुसार सिंदूर धारण करने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। वष्णु संहिता में उल्लेख मिलता है कि तिलक लगाने के लिए भिन्न-भिन्न अंगुलियां का प्रयोग अलग-अलग फल प्रदान करता है।

भगवान की पूजा के समय उनको तिलक लगाने का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार सिंदूर धारण करने से पहले कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए जैसे स्नान कर वस्त्र धारण करने के बाद उत्तर दिशा की ओर मुख करके माथे पर तिलक लगाया जाना चाहिए। विष्णु संहिता में उल्लेख मिलता है कि शुभ और वैदिक कार्य में अनामिका अंगुली, पितृ कार्य में मध्यमा, ऋषि कार्य में कनिष्ठिका तथा तांत्रिक क्रियाओं में प्रथम यानि तर्जनी अंगुली का प्रयोग किया जाना चाहिए। तिलक लगाने के लिए भिन्न-भिन्न अंगुलियां का प्रयोग अलग-अलग फल प्रदान करता है। अगर तिलक अनामिका अंगुली से लगाया जाता है तो इससे शांति मिलती है। मध्यमा अंगुली से तिलक करने पर आयु में बढ़ोत्तरी होती है, इसके अलावा अंगूठे से तिलक करना पुष्टिदायक माना गया है। तिलक चार प्रकार के होते हैं जोकि क्रमशः कुमकुम, केशर, चंदन और भस्म के लगाए जाते हैं।

- कुमकुम हल्दी चूना मिलकर बना होता है जो हमारे आज्ञा चक्र की शुद्धि करते हुए उसे कैल्शियम देते हुए ज्ञान चक्र को प्रज्ज्वलित करता है
- चंदन दिमाग को शीतलता प्रदान करते हुए मानसिक शान्ति भी देता है
- भस्मी वैराग्य की अग्रसर करते हुए मस्तिष्क के रोम कूपों के विषाणुओं को भी नष्ट करता है।

श्री हरि को लगाएं लाल चंदन का तिलक

सप्ताह में सात दिन होते हैं। यदि इन सात दिनों में भगवान को अलग-अलग तिलक लगाएं तो आपको अलग-अलग लाभ मिलेगा। इसके लिए ये उपाय आजमाएं...

सोमवार - सोमवार का दिन भगवान शंकर का दिन होता है। इसलिए भगवान को सफेद चंदन का तिलक लगाएं। इस दिन भस्म भी लगा सकते हैं।

मंगलवार - मंगल हनुमानजी का दिन माना गया है। इस दिन लाल चंदन या चमेली के तेल में घुला हुआ सिंदूर का तिलक लगाने से ऊर्जा और कार्यक्षमता में विकास होता है। इससे सकारात्मक ऊर्जा का शरीर में संचार होता है।

बुधवार - बुधवार का दिन भगवान गणेश का दिन होता है। इस दिन सूखे सिंदूर (जिसमें कोई तेल न मिला हो) का तिलक लगाना चाहिए। इस तिलक से बौद्धिक क्षमता तेज होती है।

गुरुवार - इस दिन के विशेष देवता हैं ब्रह्मा जी। गुरु को पीला या सफेद मिश्रित पीला रंग प्रिय है। इस दिन सफेद चन्दन की लकड़ी को पत्थर पर घिसकर उसमें केसर मिलाकर लेप को माथे पर लगाना चाहिए या टीका लगाना चाहिए। हल्दी का तिलक लगाना भी शुभ होता है।

शुक्रवार - शुक्रवार का दिन भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मीजी का रहता है। इस दिन का ग्रह स्वामी शुक्र ग्रह है। इस दिन लाल चंदन लगाने से जहां तनाव दूर रहता है वहीं इससे भौतिक सुख-सुविधाओं में भी वृद्धि होती है।

शनिवार - शनिवार को भैरव, शनि और यमराज का दिन माना जाता है। इस दिन विभूत, भस्म या लाल चंदन लगाना चाहिए।

रविवार - रविवार का दिन भगवान विष्णु और सूर्य का दिन रहता है। इस दिन लाल चंदन या हरि चंदन लगाएं। इससे निर्भयता आती है।

कुंडली मांगलिक है तो यह करें उपाय

भले ही कुछ लोग मांगलिक होने को लेकर बड़ा हव्वा बनाते हों लेकिन शास्त्रों के अनुसार मांगलिक होना कोई चिंता की वजह नहीं है। यदि आपके पुत्र या पुत्री की कुंडली मांगलिक है, तो घबराएं नहीं, शास्त्रों में मंगल दोष दूर करने के उपाय लिखित में उपलब्ध हैं। मांगलिक विचार का निर्णय बारीकी से किया जाना चाहिए क्योंकि शास्त्रों में मांगलिक दोष निवारण के तरीके उपलब्ध हैं। शास्त्र वचनों के जिस श्लोक के आधार पर जहां कोई कुंडली मांगलिक बनती है, वहीं उस श्लोक की परिहार (काट) के कई प्रमाण हैं। ज्योतिष और व्याकरण का सिद्धांत है कि पूर्ववर्ती कारिका से परवर्ती कारिका (बाद वाली) बलवान होती है। दोष के सम्बंध में परवर्ती कारिका ही परिहार है। इसलिए मांगलिक दोष का परिहार मिलता हो तो जरूर विवाह का फैसला किया जाना चाहिए। परिहार नहीं मिलने पर भी यदि मांगलिक कन्या का विवाह गैर मांगलिक वर से करना हो तो शास्त्रों में विवाह से पूर्व घट विवाह का प्रावधान है। मांगलिक प्रभाव वाली कुंडली से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यह दोष नहीं है बल्कि इसी मंगल के प्रभाव से जातक कर्मठ, प्रभावशाली, धैर्यवान तथा सम्मानीय बनता है।

घट विवाह है प्रभावी उपाय

कन्या की कुंडली में मांगलिक दोष का परिहार नहीं हो रहा हो तो उपाय के रुप में कन्या का प्रथम विवाह/सात फेरे किसी घट (घड़े) या वृक्ष के साथ कराए जाने का विधान है। इस प्रकार के उपाय के पीछे तर्क यह है कि मंगली दोष का मारक प्रभाव उस घट या वृक्ष पर होता है, जिससे कन्या का प्रथम विवाह किया जाता है। वर दूसरा पति होने के कारण उस प्रभाव से सुरक्षित रह पाता है। घट विवाह शुभ विवाह मुहूर्त और शुभ लग्न में पुरोहित द्वारा सम्पन्न कराया जाना चाहिए। कन्या का पिता पूर्वाभिमुख बैठकर अपने दाहिने तरफ कन्या को बिठाएं। कन्या का पिता घट विवाह का संकल्प ले। नवग्रह, गौरी गणेशादि का पूजन, शांतिपाठ इत्यादि करे। घट की षोडषोपचार से पूजा करें। शाखोच्चार, हवन, सात फेरे और विवाह की अन्य रस्म निभाएं। बाद में कन्या घट को उठाकर हृदय से सटाकर भूमि पर छोड़ दे जिससे घट फूट जाए। इसके बाद देवताओं का विसर्जन करें और ब्राह्मण को दक्षिणा दें। बाद में चिरंजीवी वर से कन्या का विवाह करें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीएम सिद्धारमैया से इस्तीफे की मांग

बेंगलूरू। कर्नाटक में भाजपा और जेडीएस मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (मुदा) घोटाले को लेकर अपना विरोध जता रही है। उसने शनिवार को 10 दिवसीय पदयात्रा शुरू की, जो सोमवार को भी जारी रही। दोनों पार्टियों ने बंगलूरू के केनगेरी से अपनी पदयात्रा की शुरुआत करी, जो मैसूर में समाप्त होगी। इस पदयात्रा के दौरान दोनों पार्टियां कथित एमयूडीए और वाल्मिकी कॉरपोरेशन में हुए घोटाले को मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगी। सोमवार को मार्च से पहले विजयेंद्र और अन्य भाजपा नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री केंगल हनुमंथैया के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। ढोल की थाप के बीच दोनों पार्टियों के बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भाजपा और जेडीएस पार्टी के झंडे और तख्तियां लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारे लगाए। विपक्षी नेताओं ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग भी की।

सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल और आप को दिया झटका

नईदिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। उच्चतम न्यायालय ने झटका देते हुए दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 10 %एल्डरमेन% को नामित करने के दिल्ली के उपराज्यपाल के फैसले को बरकरार रखा। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि उपराज्यपाल दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 'एल्डरमैन' नामित करने के संबंध में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर करीब 15 महीने तक फैसला सुरक्षित रखा। पिछले साल 17 मई को शीर्ष अदालत ने कहा था कि उपराज्यपाल को एमसीडी में 'एल्डरमैन' नामित करने का अधिकार देने का मतलब होगा कि वह निर्वाचित नगर निकाय को अस्थिर कर सकते हैं। एमसीडी में 250 निर्वाचित और 10 नामित सदस्य हैं।

लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका सम्मानपूर्वक असहमति : आप

नईदिल्ली। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 'एल्डरमैन' को लेकर उपराज्यपाल, आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में ठन गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के फैसले से खुश नहीं है। आप ने कहा कि एमसीडी में 'एल्डरमैन' नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से सम्मानपूर्वक असहमति जताते हैं, यह भारत के लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका है। फैसले की प्रति पढ़ने के बाद भविष्य के कदम पर फैसला लेंगे। 'एल्डरमैन' को नामित करने के संबंध में शीर्ष अदालत के फैसले पर कहा है। 'आप' ने एमसीडी में 'एल्डरमैन' नामित करने के उपराज्यपाल के अधिकार को लेकर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर कहा कि उच्चतम न्यायालय का फैसला सही नजीर पेश नहीं करता है, उपराज्यपाल को निर्वाचित सरकार की अनदेखी करने का अधिकार देता है।

महबूबा मुफ्ती ने घर में नजरबंद होने का दावा किया

श्रीनगर। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने सोमवार (5 अगस्त) को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की पांचवीं वर्षगांठ पर घर में नजरबंद होने का दावा किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस अवसर पर कड़ी सुरक्षा के बीच उनके पार्टी कार्यालय को बंद कर दिया गया है। पीटीआई ने मुफ्ती के हवाले से कहा, मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है, जबकि पीडीपी कार्यालय को बंद कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अल्ताफ बुखारी की अध्यक्षता वाली अपनी पार्टी का कार्यालय भी एहतियात के तौर पर दिन भर के लिए बंद कर दिया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता तनवीर सादिक ने दावा किया कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है। सादिक ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, मुझे घर पर ही हिरासत में रखा गया है, जो पूरी तरह से अनावश्यक था। मुझे किसी काम से बाहर जाना था, लेकिन मेरे गेट के बाहर पुलिसकर्मियों ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया।

उद्धव ठाकरे और फडणवीस के बीच की जुबानी जंग तेज

मुंबई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ, पूर्व मित्रों, शिवसेना (यूबीटी) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और वरिष्ठ भाजपा नेता और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस के बीच प्रतिद्वंद्विता तेज हो गई है और उनके बीच तीखी जुबानी जंग अब और अधिक कड़वी और व्यक्तिगत हो गई है। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख ने पुणे और मुंबई में कम से कम दो बैठकों में फड़णवीस की आलोचना करने के लिए कोई शब्द नहीं बोले, उनकी तुलना महत्वहीन ढेकुन (खटमल) से की और इससे छुटकारा पाने की आवश्यकता पर जोर दिया। एक अन्य बैठक में, उद्धव ने उन्हें तरबुज (तरबूज) कहा, जिसे गड्ढों में फेंक देना चाहिए। पीछे हटने वालों में से नहीं, फड़नवीस ने नागपुर में पलटवार करते हुए कहा कि उन लोगों को नजरअंदाज करना सबसे अच्छा है जो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। उद्धवजी निराश हैं। वह जिस तरह के शब्दों और भाषा का इस्तेमाल कर रहा है उससे उसकी मानसिक स्थिति का पता चलता है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बोले मनोज तिवारी

दिल्ली की जनता को भ्रमित करने में लगे रहते हैं आप के नेता

नईदिल्ली। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सवाल उठाया है कि आप के शीर्ष नेता क्यों दिल्ली की जनता को भ्रमित करने में लगे रहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कि उपराज्यपाल ने जो एल्डरमैन का निर्णय लिया उसके लिए वही सक्षम प्राधिकारी हैं। इससे,क्क के शीर्ष नेताओं के गाल पर जोरदार थप्पड़ लगा है। क्या इसके बाद आप सुधरेगी?

चीफ जस्टिस (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की यह दलील खारिज कर दी कि उपराज्यपाल एमसीडी में 'एल्डरमैन' नामित करने के संबंध में मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य हैं। उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे पर करीब 15 महीने तक फैसला सुरक्षित रखा। आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद संजय सिंह ने सोमवार को राज्य मंत्रिमंडल से परामर्श किए बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में एल्डरमेन नियुक्त करने की दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति को बरकरार रखने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना की, इसे दुर्भाग्यपूर्ण और लोकतंत्र के लिए बड़ा झटका बताया। मुझे लगता है कि यह लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि हम इस फैसले से पूरी तरह असहमत हैं।

सिंह ने मीडिया को बताया कि यह फैसला लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और सुनवाई के दौरान अदालत की टिप्पणियों के बिल्कुल विपरीत है... पूरा आदेश पढ़ने के बाद हम आगे क्या करना है, इसकी रणनीति बनाएंगे। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, दिल्ली भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें एलजी द्वारा किए गए किसी भी काम पर सवाल उठाने की आदत हो गई है।

केजरीवाल को नहीं मिली राहत याचिका खारिज

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने केजरीवाल की जमानत याचिका का निपटारा कर दिया और कहा कि वह जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जा सकते हैं। उच्च न्यायालय ने 17 जुलाई को केजरीवाल की उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था जिसमें कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। आज के आदेश में कहा गया है कि यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी उचित कारण के हुई थी। जहां तक जमानत आवेदन का सवाल है तो इसे ट्रायल कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया जाता है। अदालत ने केजरीवाल और सीबीआई के वकील की दलीलें सुनने के बाद 29 जुलाई को आप नेता की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

निर्धारित समय सीमा के अनुसार जम्मू-कश्मीर में हो चुनाव: खरगे

नई दिल्ली। कांग्रेस ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में चुनाव सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार होने की मांग की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आरोप लगाया कि भाजपा की नीति न तो 'कश्मीरियत' का सम्मान करने वाली है और न ही 'जम्हूरियत' (लोकतंत्र) को बरकरार रखने वाली है। बता दें कि केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 2019 में निष्प्रभावी बना दिया था। इसके साथ ही सरकार ने तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से दो केंद्र-शासित प्रदेश-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था।

मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर भाजपा की नीति न तो 'कश्मीरियत' का सम्मान करने वाली है और न ही 'जम्हूरियत' को कायम रखने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि मोदी सरकार ने दावा किया था कि इस कदम से जम्मू-कश्मीर को पूर्ण रूप से एकीकृत करने, क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आतंकवाद को रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल अलग है।

खरगे ने आगे कहा, 2019 के बाद से 683 घातक आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप 258 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए और 170 नागरिकों की जान चली गई। विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की तीसरे कार्यकाल की शपथ के बाद से जम्मू क्षेत्र में 25 आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसमें 15 सैनिकों की जान चली गई और 27 घायल हो गए। उन्होंने दावा किया कि पिछले कुछ वर्षों में कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याएं काफी बढ़ गई हैं।

जम्मू कश्मीर में 2019 से ही 65 प्रतिशत सरकारी विभाग पद खाली हैं। यहां बेरोजगारी दर 10 प्रतिशत है। 2021 में नयी औद्योगिक नीति लागू होने के बावजूद महज तीन प्रतिशत निवेश ही जमीन पर उतर पाया है। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज, 2015 के तहत 40 प्रतिशत परियोजनाएं लंबित हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोग सामान्य स्थिति के लिए तरस रहे हैं। यहां के लोगों ने अपनी स्थिति भारत जोड़ो अभियान के दौरान राहुल गांधी के सामने रखी थी। खरगे ने इस बात पर भी जोर दिया कि कांग्रेस यहां के लोगों के साथ खड़ी है।

किसानों के खून से सने हैं कांग्रेस के हाथ: शिवराज

नईदिल्ली। राज्यसभा में आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों पर किए गए अत्याचारों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आंकड़े बताते हुए शिवराज ने कहा कि जब यही कांग्रेस अलग-अलग राज्यों में सत्ता में थी तो किसान मारे गए। 1986 में जब बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, तब गोलीबारी में 23 लोग मारे गये थे। 1988 में इंदिरा गांधी की पुण्य तिथि पर दिल्ली में 2 किसानों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि 1988 में उन्होंने मेरठ में किसानों पर फायरिंग की और 5 किसान मारे गये।

शिवराज सिंह चौहान यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि 23 अगस्त 1995 हरियाणा में इनकी सरकार ने गोली चलाई और छह किसान मारे गए। इसी तरह 19 जनवरी 1998 को मुलताई, एमपी में किसानों पर गोली चली कांग्रेस की सरकार थी, 24 किसान मारे गए। उन्होंने साफ तौर पर तंज भरे लहजे में कहा कि मैने किसी को छेड़ा नहीं, लेकिन जो छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हम किसान सम्मान निधि पर चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस ने किसानों को सीधी मदद की बात तो की लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना कांग्रेस ने कभी नहीं बनाई। ये योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई। अपना हमला जारी रखते हुए कहा कि वे (विपक्ष) नहीं समझेंगे लेकिन छोटे किसानों के लिए 6000 रुपये की राशि मायने रखती है। उन्होंने कहा कि इस किसान सम्मान निधि के कारण किसान आत्मनिर्भर हुए हैं, किसान सशक्त भी हुए हैं और किसानों का सम्मान भी बढ़ा है। वे (विपक्ष) किसानों का सम्मान नहीं देख सकते। उन्होंने कहा कि मैंने देश के सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण पढ़े, पर कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों की प्राथमिकता में कभी किसान नहीं रहा। जो दिल में होता है, वही जुबान पर आता है।

वक्फ अधिनियम में संशोधन लाने की तैयारी में सरकार

नईदिल्ली। जानकारी के मुताबिक भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों को सीमित करने के लिए वक्फ अधिनियम में संशोधन लाने की तैयारी में है। इसको लेकर संसद में संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि अल्पसंख्यक आबादी के कई वर्गों द्वारा पैदा की जा रही इस आशंका को दूर करने के लिए कि यह विधेयक अल्पसंख्यकों के अधिकारों को छीन लेगा, आगामी कानून केवल मुस्लिम समर्थक होगा।

घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों ने बताया कि कई गरीब मुस्लिम और खासकर मुस्लिम महिलाएं न्याय के लिए सरकार के पास पहुंची हैं। उन्होंने यह भी व्यक्त किया है कि कैसे ये संपत्तियां बहुत शक्तिशाली लोगों के नियंत्रण में हैं और आम आदमी के दुखों के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं है। अधिनियम पहली बार 1954 में लाया गया था, 1995 में और फिर 2013 में संशोधित किया गया था। पहले के रूप में, ट्रिब्यूनल का शब्द अंतिम और बाध्यकारी था, लेकिन अब प्रस्तावित नए संशोधन के साथ जो कोई भी आगे बढ़ना चाहता है वह किसी भी विवाद की स्थिति में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। एक सूत्र ने बताया कि सरकार का इन संपत्तियों को मुसलमानों से छीनने का कोई इरादा नहीं है, आखिरकार, इन संपत्तियों का उपयोग केवल मुस्लिम समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए ही किया जा सकता है।

खेल
प्रमुख समाचार

ओलंपिक समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी मनु

पेरिस। स्टार महिला निशानेबाज मनु भाकर पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक होंगी। मनु ने पेरिस खेलों में दो कांस्य पदक जीतकर इतिहास रचा था। मनु ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर देश का इन खेलों में पदक का खाता खुलवाया था। इसके बाद उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता था।

भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अधिकारी ने कहा, %हां, मनु को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया था और वह इसकी हकदार हैं।% हरियाणा की 22 वर्षीय निशानेबाज ने इससे पहले कहा था कि भारत का ध्वजवाहक बनना सम्मान की बात की है। मनु के अलावा भारत को स्वप्निल कुसाले ने पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्री पोजिशन में कांस्य पदक दिलाया था। आईओए ने अभी तक पुरुष ध्वजवाहक की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी घोषणा भी कर दी जाएगी।

मनु एक ओलंपिक में दो पदक जीतने वाली भारत की पहली एथलीट हैं। वहीं, मनु ओलंपिक में भारत की ओर से सबसे सफल एथलीट में से भी एक हैं। मनु के अलावा अब तक किसी भारतीय एथलीट ने एक ओलंपिक में दो पदक नहीं जीते हैं। सुशील कुमार और शटलर पीवी सिंधू के नाम दो-दो पदक हैं, लेकिन ये अलग-अलग ओलंपिक में आए हैं। सुशील ने 2008 बीजिंग (कांस्य) और 2012 लंदन (रजत) ओलंपिक में दो पदक जीते थे, जबकि सिंधू ने 2016 रियो (रजत) और 2020 टोक्यो ओलंपिक (कांस्य) में दो पदक जीते थे। मनु ने सभी को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच दिया था। इसी के साथ वह एक ओलंपिक में दो या इससे ज्यादा पदक जीतने वाले एथलीट्स की लिस्ट में भी शामिल हो गई थीं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 2222 अंक टूटा निफ्टी का भी हाल बुरा

नईदिल्ली। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंकाओं के बीच वैश्विक बाजारों की भारी बिकवाली का दबाव दलाल स्ट्रीट पर भी देखने को मिला। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में भूचला आ गया और बेंचमार्क इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी लगभग 3 प्रतिशत टूट गए। 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 2,222.55 अंक या 2.74 प्रतिशत गिरकर एक महीने के निचले स्तर 78,759.40 पर बंद हुआ, जो 4 जून, 2024 के बाद से एक दिन की सबसे खराब गिरावट है। दिन के दौरान, यह 2,686.09 अंक या 3.31 प्रतिशत गिरकर 78,295.86 पर आ गया। वहीं, दूसरी तरफ एनएसई निफ्टी 662.10 अंक या 2.68 प्रतिशत लुढ़ककर 24,055.60 पर बंद हुआ। दिन के दौरान यह 824 अंक या 3.33 प्रतिशत गिरकर 23,893.70 पर आ गया। 4 जून, 2024 के बाद से निफ्टी में भी एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई।

गौतम अडानी लेने वाले हैं संन्यास?

नईदिल्ली। दिग्गज कारोबारी और अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी को लेकर कई चर्चाएं इन दिनों हो रही है। गौतम अडानी सुर्खियों में लगातार बने हुए है। इस बार चर्चा है कि गौतम अडानी आने वाले वर्षों में खुद रियाटर होकर अपनी संपत्ति और कारोबार की कमान अपने उत्तराधिकारी को सौंप देंगे। गौतम अडानी ने अपने समूह के लिए उत्तराधिकार योजना तैयार की है, जिसके अनुसार 62 वर्षीय अडानी 70 वर्ष की आयु में पद छोड़ देंगे और अपने व्यापारिक साम्राज्य का नियंत्रण अपने बेटों और उनके चचेरे भाइयों को 2030 के प्रारंभ तक सौंप देंगे। ब्लूमबर्ग न्यूज़ से बात करते हुए गौतम अडानी ने कहा कि वे व्यवसाय की स्थिरता के लिए एक सुनियोजित बदलाव पर बहुत ध्यान केंद्रित कर रहे थे। उन्होंने कहा, व्यवसाय की स्थिरता के लिए उत्तराधिकार बहुत, बहुत महत्वपूर्ण है।

जुलाई में 3.20 लाख गाड़ियों की हुई बिक्री

नईदिल्ली। नए मॉडल की पेशकश और बढ़ी हुई छूट से भारत में यात्री वाहनों की रिटेल बिक्री जुलाई में सालाना आधार पर 10 प्रतिशत बढ़ी। उद्योग निकाय फाडा ने सोमवार को यह जानकारी दी। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार जुलाई में कुल यात्री वाहन खुदरा बिक्री बढ़कर 3,20,129 इकाई हो गई, जबकि जुलाई 2023 में यह 2,90,564 इकाई थी। फाडा के उपाध्यक्ष सी. एस. विग्नेश्वर ने कहा, '' डीलरों ने बताया कि उन्हें अच्छे उत्पाद उपलब्ध होने, आकर्षक योजनाओं और उत्पादों की व्यापक श्रृंखला से लाभ मिला है।'' उन्होंने कहा कि भारी बारिश, उपभोक्ता भावना में कमी और तीव्र प्रतिस्पर्धा के कारण चुनौतियां उत्पन्न हुईं, लेकिन अधिक प्रचार तथा बढ़ी छूट के जरिये बिक्री को बनाए रखने में कामयाबी हासिल हुई। जुलाई में दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 17 प्रतिशत बढ़कर 14,43,463 इकाई रही, जो जुलाई 2023 में 12,31,930 इकाई थी।

सर्विस सेक्टर की वृद्धि दर में जुलाई में मामूली गिरावट

नईदिल्ली। भारत के सर्विस सेक्टर की वृद्धि जून की तुलना में जुलाई में थोड़ी धीमी रही। एक मासिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई है। मौसमी रूप से समायोजित एचएसबीसी इंडिया भारत सेवा पीएमआई कारोबारी गतिविधि सूचकांक जुलाई में 60.3 रही जबकि जून में यह 60.5 थी। खरीद प्रबंधक सूचकांक की भाषा में 50 से ऊपर अंक का मतलब गतिविधियों में विस्तार से और 50 से कम अंक का आशय संकुचन से होता है। एचएसबीसी के मुख्य अर्थशास्त्री (भारत) प्रांजुल भंडारी ने कहा, '' जुलाई में सेवा क्षेत्र की गतिविधि थोड़ी धीमी गति से बढ़ी, नए कारोबार में और वृद्धि हुई जो मुख्य रूप से घरेलू मांग से प्रेरित रही। सेवा कंपनियां आने वाले वर्ष के लिए आशावादी हैं।'' सितंबर 2014 में इस सर्वेक्षण की शुरुआत के बाद से नए निर्यात ठेकों में तीसरी सबसे तेज वृद्धि हुई है।

निवेशकों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए

हर्ष रूंगटा

दो दोस्त, राम और श्याम, एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे जब लुटेरों ने यात्रियों को लूटना शुरू कर दिया। श्याम पर राम का कुछ पैसा बकाया था। इससे पहले कि लुटेरे उन तक पहुंच पाते, श्याम ने अपनी जेब से पैसे निकाले और राम को अपना कर्ज चुका दिया। राम पैसे लेने से इंकार नहीं कर सका, भले ही वह जानता था कि वह जल्द ही इसे लुटेरों के हाथों खो देगा। इंडैक्सेशन (सूचीकरण) लाभों ने मुझे इस मनोरंजक कहानी की याद दिला दी। दुनिया भर में पूंजीगत लाभ कराधान 3 मुख्य तरीकों से लगाया जाता है। प्रत्येक विधि यह स्वीकार करना चाहती है कि 'वास्तविक' पूंजीगत लाभ 'कागजी' पूंजीगत लाभ से कम है। कागजी पूंजीगत लाभ की गणना बिक्री प्रतिफल से खरीद मूल्य घटाकर की जाती है।

पहला और सबसे लोकप्रिय तरीका ऐसे कागजी पूंजीगत लाभ पर कर लगाने के लिए रियायती दर रखना है। दूसरी विधि कागजी पूंजीगत लाभ के केवल एक हिस्से पर सामान्य कर दरों पर कर लगाना है (उदाहरण के लिए, कागजी पूंजीगत लाभ के केवल 50 प्रतिशत पर सामान्य दरों पर कर लगाया जाता है)। तीसरी विधि, जिसका हमने अनुसरण किया, मुद्रास्फीति के लिए खरीद लागत को समायोजित करना है, उसके बाद मुद्रास्फीति-समायोजित पूंजीगत लाभ पर रियायती दर पर कर लगाना है।

वास्तव में, भारत ने 1992 तक दूसरी विधि (पूंजीगत लाभ का 50 प्रतिशत सामान्य दरों पर कर) का पालन किया। 1992 के आसपास संकट-युग के बजट ने वर्तमान सूचकांक पद्धति की शुरूआत की। उस परिवर्तन के समय विजेता और हारने वाले दोनों थे। उच्च-रिटर्न निवेशकों (1981 में

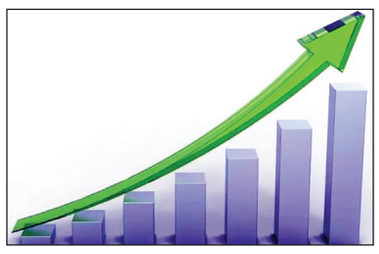

खरीद मूल्य 260 हजार और 1992 में बिक्री मूल्य 15 लाख और प्रति वर्ष 21 प्रतिशत रिटर्न थी) को परिवर्तन के कारण नुकसान हुआ। कम-रिटर्न वाले निवेशकों की तुलना में (1989 में खरीद मूल्य 24 लाख और 1992 में बिक्री मूल्य 5 लाख और रिटर्न 9 प्रतिशत प्रति वर्ष थी) अब, चीजें पूर्ण चक्र में आ गई हैं। कल के विजेता (कम रिटर्न वाले निवेशक) आज हारे हुए महसूस कर रहे हैं और इसके विपरीत ऐसे किसी भी बदलाव में विजेता और हारने वाले दोनों होंगे।

12.5 प्रतिशत की दर पर जाने के लिए सरकार को दोष देने का यही एकमात्र कारण नहीं हो सकता है, जो वैश्विक स्तर पर निम्न स्तर पर है। सरकार ने 2018 के लिए कराधान सूची को फिर से लागू किया, तो उसे 2018 की तारीख तक अर्जित लाभ पर छूट मिलेगी। वास्तव में, जब सरकार ने 2018 में सूचीबद्ध हिस्सेदारी में कराधान को फिर से शुरू किया, तो उसने 2018 के बजट की तारीख तक अर्जित पूंजी को छूट देने का ध्यान रखा। यह चर्चा का विषय नहीं है क्योंकि इसमें पहले से छूट प्राप्त हिस्सेदारी पर केवल भविष्य के लाभ को कम करने की कोशिश की गई थी। कर स्थिरता बनाए रखने के लिए सरकार की प्रतिष्ठा इसी तरह बढ़ जाएगी यदि इसमें एक अपमानजनक सूर्यास्त खंड शामिल हो।

सबसे अच्छा समाधान वह होगा जो 2018 में अपनाया गया था जिसके अनुसार 31 मार्च, 2024 तक लागत सूचकांक की अनुमति देना था। दूसरा सबसे अच्छा विकल्प यह होगा कि निवेशकों को पुरानी इंडैक्सेशन व्यवस्था के तहत अपने निवेश से बाहर निकलने के लिए 31 मार्च, 2025 तक का समय दिया जाए। यह समय 1 फरवरी के सामान्य बजट में स्वत: ही स्वीकृत हो जाता।

निवेशकों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह चुनाव के बाद जुलाई का बजट है। कर स्थिरता के लिए प्रतिष्ठा में लाभ सरकार को होने वाले किसी भी राजस्व नुकसान की भरपाई से कहीं अधिक होगा।हालांकि कार्यान्वयन का एक संवेदनशील तरीका ऐसे परिवर्तनों के लिए मार्ग को सुगम बनाने में काफी मदद कर सकता है। उम्मीद है कि सरकार केवल तकनीकी रूप से सही होने तक ही सीमित नहीं रहेगी और इन बदलावों में ढील देने की दलीलों पर उचित विचार करेगी।

मुख्यमंत्री ने भोरमदेव में हजारों कावड़ियों का पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत

भोरमदेव/रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के प्राचीन, पुरातात्विक, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल बाबा भोरमदेव मंदिर में पवित्र सावन मास के अवसर पर हजारों कावड़ियों का हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में मुख्यमंत्री श्री साय ने हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष के साथ कावड़ियों और श्रद्धालुओं का स्वागत किया और उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री के साथ उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने भी कावड़ियों का अभिनंदन किया। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं हेलीकॉप्टर से शिवभक्त कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री साय ने इस अद्वितीय मौके पर भोरमदेव बाबा भगवान शिव जी की विशेष पूजा-अर्चना और रुद्राभिषेक भी किया, जिसमें उन्होंने प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली की कामना की।

मुख्यमंत्री साय और उपमुख्यमंत्री शर्मा ने मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से मुलाकात की और भंडारा स्थल पर पहुंचकर अपने हाथों से श्रद्धालुओं को खीर, पुड़ी, चावल और प्रसाद वितरित किया। इस दौरान पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती सुशीला राम कुमार भट्ट, जनपद अध्यक्ष श्री इंद्राणी चंद्रवंशी, पूर्व विधायक श्री अशोक साहू, और नगर पंचायत अध्यक्ष श्री मनहरण कौशिक ने भी बाबा भोरमदेव भगवान शिव की पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया।

सावन में शिव भक्तों के लिए ऐतिहासिक आयोजन- इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सर्वप्रथम सभी भक्तजनों को सावन मास की शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि सावन के तीसरे सोमवार को भगवान भोलेनाथ के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उन्होंने प्रदेश के सभी लोगों की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की है। पवित्र सावन माह में शिव भक्तों के लिए यह ऐतिहासिक आयोजन रहा। कबीरधाम जिले में स्थित बाबा भोरमदेव मंदिर के साथ-साथ, बुढ़ा महादेव और डोंगरिया के जलेश्वर महादेव जैसे ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों पर भी हर साल हजारों कावड़ियों द्वारा जलाभिषेक किया जाता है। इस अवसर पर, अमरकंटक से शिव भक्त पदयात्रा कर छत्तीसगढ़ के विभिन्न शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। बाबा भोरमदेव मंदिर 11वीं शताब्दी का एक प्राचीन, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का स्थल है, जहां हर साल सावन मास में कावड़ियों की पदयात्रा का आयोजन होता है। इस कावड़ यात्रा में मध्यप्रदेश के अमरकंटक से मां नर्मदा का पवित्र जल लेकर भक्तजन कठिन मार्गों से गुजरते हुए बाबा भोरमदेव, जलेश्वर महादेव और पंचमुखी बूढ़ा महादेव में जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान वे बोल बम के जयघोष के साथ भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में इस वर्ष की कावड़ यात्रा

भाजपा सरकार धर्मद्रोही सरकार हैः दीपक

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार पर धर्म द्रोही होने का आरोप लगाते हुए कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में छत्तीसगढ़ के धार्मिक स्थलो के संरक्षण और संवर्धन के लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित करने की व्यवस्था शुरु की थी, उन्हें दुर्भावना पूर्वक बंद करके सनातन संस्कृति का अपमान कर रही है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के समय चंदखुरी स्थित माता कौशल्या के दुनिया के एकमात्र मंदिर जो राजधानी से महत्व 27 किलोमीटर की दूरी पर है उसके जीर्णोद्धार का काम किया। उत्तर में कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका से लेकर दक्षिण में बस्तर के सुकमा में रामाराम तक पर्यटक सुविधाएं विकसित की। पहुंच मार्ग बनाये, सड़कों के दोनों तरफ फलदार वृक्षों का रोपण करवाया। राजीम, चंपारण, शिवरीनारायण और चंदखुरी में छत्तीसगढ़ के भाषा प्रभु श्री राम की भव्य मूर्तियां स्थापित की गई। सुकमा के रामाराम में छत्तीसगढ़ का पहला रॉक गार्डन बना जहां पर प्रभु श्री राम के जीवन चरित की भव्य झांकी बनाई गई है। रामा-राम में जामवंत गुफा, सीता कुटिया का निर्माण करने के साथ ही चिटमिटिन माता के मंदिर का जिर्णोद्धार पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने करवाया। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ के 75 स्थलों को चिन्हित कर उनमें से 51 स्थलों पर राम काज की शुरूआत की गई। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से पिछले 8 महीने से राम वन गमन पथ के संरक्षण और संवर्धन का काम पूरी बंद कर दिया गया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के 11 में से 10 सांसद हैं लेकिन मोदी सरकार के केंद्रीय रामायण परिपथ में एक भी स्थल शामिल नहीं है। पूर्वाग्रह से ग्रसित मोदी सरकार लगातार छत्तीसगढ़ उपेक्षा कर रही है लेकिन दलीय चाटुकारिता में भारतीय जनता पार्टी के नेता मौन है। छत्तीसगढ़ कौशल प्रदेश कहलाता है, बस्तर का क्षेत्र ऐतिहासिक तौर पर दंडकारण्य कहा जाता है। प्रभु श्री राम ने वनवास का अधिसंख्यक समय छत्तीसगढ़ में ही गुजरे हैं, माता कौशल्या का एकमात्र मंदिर भी छत्तीसगढ़ में ही स्थित है, जहा जाने का समय भाजपा के नेताओं के पास नहीं है। शिवरीनारायण में प्रभु श्री राम ने माता शबरी के झूठे बेर ग्रहण कर सामाजिक न्याय का संदेश दिया है.

सनातन धर्म विरोधी है कांग्रेसः भारती

रायपुर। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री रामजी भारती ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस शुरू से ही सनातन धर्म विरोधी रही है। कांवड़ यात्रियों पर मुख्यमंत्री साय के हाथों हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा किए जाने पर कांग्रेसियों की टिप्पणी को सनातन विरोधी प्रलाप बताकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी के स्वागत में 2 किलोमीटर तक 6 हजार किलो गुलाब की पंखुड़ियों से सजाकर सामंती चरित्र का शर्मनाक प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियो को कांवड़ यात्रियों के पुष्पवर्षा से स्वागत और अभिनंदन पर पेट में दर्द हो रहा है।

भाजपा प्रदेश महामंत्री ने कहा कि कांग्रेसियों की राजनीतिक दुकान सनातन विरोध और हिन्दुत्व के प्रति घृणा से सजी है और रह-रहकर अपनी इन दुकानों में बैठकर सनातन संस्कृति के खिलाफ विष-वमन करते रहना कांग्रेसियों की लत में शुमार है। भूपेश सरकार के राज में इलाज के अभाव में प्रदेश के 39 हजार बच्चों की मौत से कलंकित कांग्रेस आज डायरिया के नाम पर घड़ियाली आ×सू बहाकर ओछी राजनीति कर रही है, जबकि प्रदेश की भाजपा सरकार इस बीमारी के प्रसार पर अंकुश लगाने के तमाम उपायों पर पूरी संजीदगी और संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।

रामजी भारती ने ने कहा कि सनातन के खिलाफ खुद को खड़ा बताने के लिए अब कांग्रेसी कार्ल मार्क्स के धर्म को अफीम बताए जाने तक को जस्टीफाई करने में जरा भी शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं। इससे यह भी साफ हो गया है कि वामपंथियों के रचे चक्रव्यूह में फंसी कांग्रेस विचारों से पूरी तरह से कंगाल हो चुकी है कि अब वामपंथ के उधार के विचारों की बैसाखी पर अपने राजनीतिक वजूद को बचाने के ये घृणित उपक्रम कांग्रेस की नियति हो चले हैं।

भारती ने कहा कि कभी प्रदेश की राजधानी में प्रियंका वाड्रा के स्वागत में 2 किलोमीटर तक की सड़क को 6 हजार किलोग्राम गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों से कालीन की तरह सजाकर अपने सामंती चरित्र का शर्मनाक प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसियो को आज काँवर यात्रियों का पुष्पवर्षा से स्वागत और अभिनंदन करने पर पेट में रह-रहकर मरोड़ उठ रहा है! यह पाखंड कांग्रेस के सनातन और हिन्दुत्व विरोधी राजनीतिक चरित्र को बेनकाब करने के लिए पर्याप्त है।

भाजपा के सहयोग केंद्र में जनसमस्याओं का निराकरण

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश कार्यालय में आयोजित सहयोग केंद्र में प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री, मंत्री और भाजपा पदाधिकारी समस्याओं और आवेदनों का त्वरित निराकरण कर रहे हैं। भाजपा के मंत्री लगातार सहयोग केंद्र में लगातार शामिल हो रहे है और समस्याओं एवं आवेदन का त्वरित निराकरण कर रहे हैं।

इसी कड़ी में आज सोमवार को प्रदेश के वनमंत्री केदार कश्यप जनसहयोग केंद्र पहुंचे।

जनसमस्याओं को सुनकर उसके निराकरण के लिए विभागीय अधिकारियों से फोन पर बातचीत कर उचित दिशा निर्देश दिए।

उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि विभागीय समस्यों के साथ अन्य विभाग से जुड़े मुद्दे भी आ रहे हैं। प्रमुख रूप से सहकारिता से जुड़े कांग्रेस शासन के अनियमितताओं पर सूक्ष्मता से जांच के आवेदन, प्रधानमंत्री आवास योजना, सार्वजनिक मंच, मंदिर, सड़क निर्माण, सामाजिक हित से जुड़े विषयों पर आवेदन प्राप्त हुए हैं।

सहयोग केंद्र में प्रदेश महामंत्री विकास महतो, रूपनारायण सिन्हा, विजय शंकर मिश्रा सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़/राजधानी प्रमुख समाचार

भाजपा सरकार बनने के बाद व्यापारियों को परेशान किया जा रहा

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जब से राज्य में भाजपा सरकार बनी है सरकार उद्योग व्यापार को चौपट करने वाला निर्णय ले रही है। जिन व्यापारियों उद्योगपतियों को दिये जाने वाले टैक्स के पैसे से सरकार विकास और राहत के काम करती है। उन्हीं व्यापारियों को परेशान किया जाना गलत है? सात महिने में लगातार व्यापारियों के यहां सरकार द्वारा जीएसटी के छापे मारी करवाया जा रहा है। बिजली बिल बढ़ोत्तरी के कारण उद्योगो में एक सप्ताह से ताला बंदी हो गयी है। 2 लाख मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि भाजपा नेता के द्वारा व्यापारियों को टैक्स चोर कहना निंदनीय है ये वही व्यापारी हैं जिनके द्वारा दिये गए टैक्स से राज्य का खजाना भरता है और विकास कार्य होता है। व्यापारी वर्ग लगातार अनियमितता जीएसटी से परेशान और हताश होकर केंद्र सरकार से कई बार गुहार लगाये हैं कई सुझाव दिए हैं लेकिन उसे पर केंद्र सरकार ने अमल नहीं किया है और आज जो जीएसटी का छापा व्यापारियों के यहां पड़ रहा है यह सिर्फ भाजपा के वसूली के लिए पड़ रहा हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि जिस समय जीएसटी लागू किया गया.

नई शिक्षा नीति से देश की तरक्की में बढ़ेगा युवाओं का योगदान

रायपुर। देश की तरक्की की राह में युवाओं का योगदान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लागू की गई। नई शिक्षा नीति का छत्तीसगढ़ में क्रियान्वयन हो रहा है। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा बलौदाबाजार जिले के विभिन्न कॉलेजों में आयोजित दीक्षारंभ समारोह को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में नई शिक्षा नीति का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा रहा है। राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि नई शिक्षा नीति में नौकरी की जगह स्वरोजगार पर जोर दिया गया है, ताकि व्यक्ति आत्मनिर्भर होकर खुद को नौकरी के बजाय अन्य लोगों को नौकरी प्रदान कर सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा नीति में मातृभाषा में पढ़ाई के साथ-साथ देश की संस्कृति, सभ्यता को महत्व दिया गया है, जिससे छात्रों में गौरवशाली संस्कृति से परिचित हो सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में नवीनतम तकनीकी ज्ञान का भी समावेश किया गया है।

रमन सरकार के पापों का प्रायश्चित करने मनाया हरेली तिहार

रायपुर। भाजपा सरकार द्वारा हरेली तिहार उत्सव के आयोजन पर तंज करते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में पूर्व में 15 साल रमन सिंह की सरकार रही, तब भाजपा के नेताओं को न हरेली याद आया न तिजा पोरा। छत्तीसगढ़ की प्रथा परंपरा और संस्कृति का ख्याल उस दौरान भारतीय जनता पार्टी को नहीं रहा, अब साय सरकार 15 साल के पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के पाप धोने, सरकारी आयोजन कराने मजबूर है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से हरेली, तीजा पोरा, गोवर्धन पूजा और विश्व आदिवासी दिवस पर न केवल अवकाश घोषित किया गया बल्कि राजधानी में मुख्यमंत्री आवास से लेकर जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर छत्तीसगढ़िया तीज त्यौहारो का सरकारी आयोजन करने की शुरुआत हुई। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता कांग्रेस सरकार के आयोजनो की निंदा करते थे, उपेक्षा करते थे, हिकारत भरी नज़रों से देखते थे, आज छत्तीसगढ़ी त्योहारों के आयोजन करने के लिए बाध्य हुए हैं। यह छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान और आत्मसम्मान की जीत है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की छत्तीसगढ़िया विरोधी अहंकार की हार है।

वक्फ संशोधन देश के मुसलमानो को न्याय देने वाला कानून

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश प्रभारी एवं भाजपा नेता डॉ. सलीम राज ने केन्द्र की एन.डी.ए. सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम में किये गये संशोधन का स्वागत करते हुए कहा कि, यह कानून देश के गरीब मुसलमानों को न्याय देने वाला कानून है। वक्फ एक्ट में संशोधन एवं सुधार समय के अनुसार होना चाहिये, वर्तमान में जो विसंगतिया है उसे दूर किये जाने के लिये यह कानून लाया जा रहा है, जिसका हम माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी एवं एन.डी.ए. सरकार का स्वागत करते है। उन्होने कहा कि, वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों के उत्थान के लिये बनाया गया था वक्फ संपत्ती को ईश्वर (अल्लाह) की संपत्ती माना जाता है। उसके विपरित वक्फ एक्ट की शक्तियों का सिर्फ दुरूपयोग ही हो रहा है। देश के संघराज्य एवं राज्य वक्फ बोर्डों को प्राप्त असीमित अधिकार एवं शक्तियों के कारण यह मजहबी जमींदारी, भ्रष्टाचार एवं भूमाफियाओ को संरक्षण दे रहा है। वर्तमान वक्फ एक्ट पूरी तरह से निरंकुश है और इससे आम मुसलमानों को कोई फायदा नही हो रहा है। संशोधित वक्फ कानून जमींदारी की दादागिरी तथा भूमाफिया एवं अतिक्रमणकारियों पर नकेल कसने वाला कानून है। वक्फ संपत्तीयों के मामलों में शासन को अधिकार व शक्तियां प्रदान करने वाला कानून है। उन्होने कहा कि, वक्फ अधिनियम की धारा 09 एवं 14 में बदलाव से बोर्ड और अधिक सशक्त

छत्तीसगढ़ में 670.6 मिमी वर्षा दर्ज

रायपुर। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक एक जून 2024 से अब तक राज्य में 670.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। राज्य के विभिन्न जिलों में 01 जून 2024 से आज 05 अगस्त सवेरे तक रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार बीजापुर जिले में सर्वाधिक 1504.7 मिमी और सरगुजा जिले में सबसे कम 309.8 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी है। राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सूरजपुर जिले में 538.0 मिमी, बलरामपुर में 834.3 मिमी, जशपुर में 507.1 मिमी, कोरिया में 550.0 मिमी, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 568.2 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। इसी प्रकार, रायपुर जिले में 598.5 मिमी, बलौदाबाजार में 741.2 मिमी, गरियाबंद में 646.4 मिमी, महासमुंद में 499.2 मिमी, धमतरी में 667.8 मिमी, बिलासपुर में 621.2 मिमी, मुंगेली में 668.4 मिमी, रायगढ़ में 548.1 मिमी, सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 342.8 मिमी, जांजगीर-चांपा में 597.0 मिमी, सक्ती 513.7 कोरबा में 775.4 मिमी, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 598.3 मिमी, दुर्ग में 440.9 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गयी। कबीरधाम जिले में 547.6 मिमी एक जून से अब तक रिकार्ड की गई।

राज्य बाल संरक्षण समिति की आमसभा सम्पन्न

रायपुर। किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत गठित राज्य बाल संरक्षण समिति की कार्यकारिणी तथा आमसभा बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग एवं पदेन अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण समिति श्रीमती शम्मी आबिदी की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आज सम्पन्न हुई। सचिव महिला एवं बाल विकास द्वारा बैठक में बाल संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर एवं विभिन्न विभागों के साथ समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। संयुक्त

संचालक, मिशन वात्सल्य द्वारा वर्तमान में राज्य में बाल संरक्षण के क्षेत्र में किये जा रहे विभिन्न कार्यों, किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 के क्रियान्वयन हेतु संचालित मिशन वात्सल्य के तहत प्रदान की जा रही संस्थागत एवं गैर संस्थागत देखरेख सेवाओं की जानकारी का प्रस्तुतीकरण किया गया।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में 93 बाल देखरेख संस्थाएं संचालित हैं, जिनमें देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 67 एवं विधि से संघर्षरत बच्चों के लिए 26 संस्थाएं संचालित हैं। इन संस्थाओं में 2046 बच्चे निवासरत हैं, जिनमें से 1318 बच्चे शाला में अध्ययनरत एवं 29 बच्चे ओपन स्कूल के माध्यम से परीक्षा देंगे। वर्ष 2023-24 में बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत 10वी के 32 एवं 12वी के 23 बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। आगामी शिक्षा सत्र के विषय चयन हेतु 136 बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट कराया गया। कोंडागांव एवं महासमुंद जिले के बच्चों द्वारा जुडो, तीरंदाजी खेलों में प्रदर्शन किया गया। जिसके फलस्वरूप सांई हॉस्टल एवं खेल अकादमी में प्रवेश प्रदाय किया गया है। सचिव महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संस्थागत देखरेख में निवासरत बालकों के सर्वांगीण विकास हेतु अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने, कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने, बच्चों की समुचित स्वास्थ्यगत देखभाल करने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग एवं संबंधित विभागों की संयुक्त कार्ययोजना बनाकर प्रभावी कियान्वयन हेतु निर्देशित किया गया। खेल एवं युवा कल्याण विभाग को उनकी गतिविधियों में इन बच्चों को शामिल करने के निर्देश दिये गये।

राजस्व मंत्री ने पीएम आवास के हितग्राही को कराया गृह प्रवेश

क्रराजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री टंकराम वर्मा हरेली त्यौहार के पावन अवसर पर विकासखंड बलौदाबाजार के ग्राम सकरी में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के हितग्राही को नवनिर्मित आवास का फीता काटकर गृह प्रवेश कराया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सुंदर मकान बनाने पर गिरजाशंकर एवं उसके परिवार को शुभकामनायें दी। उन्होंने नवनिर्मित मकान के आंगन में कटहल और अमरुद के पेड़ लगाए। इस अवसर पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, पूर्व संसदीय सचिव डॉ सनम जांगड़े, कलेक्टर श्री दीपक

सोनी, सीईओ जिला पंचायत सुश्री दिव्या अग्रवाल उपस्थित थे।

पेशे से राज मिस्त्री हितग्राही गिरजाशंकर ने बताया कि पहले कच्चा मकान था। जिसमें कई प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता था। पक्का मकान का सपना था, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसी बीच वर्ष 2020- 21 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत आवास स्वीकृत हुआ। पहली किश्त मिलने पर मकान बनाना शुरू किया तीन किश्त में कुल एक लाख बीस हजार रुपये मिले।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.